■ RNI No. 58061/93 ■ वर्ष - 21 ■ अंक - 198 ■ पृष्ठ - 8 ■ रु. 5/- बेंगलूरु » शुक्रवार » 13-02-2026 ■ www.dakshinbharat.com ■ Email : news@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूरु और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित

5 परमाणु ऊर्जा के लिए 'पहले सुरक्षा, तब उत्पादन' का सिद्धांत : जितेंद्र सिंह

6 डीपफेक का धोखा और डिजिटल सख्त नियमों की अनिवार्यता

7 मधुर भंडारकर की 'द वाइव्स' में 'महक' बनेंगी मौनी रॉय

फर्स्ट टेक

रूस ने मैसेजिंग ऐप को पूरी तरह से बाधित करने की कोशिश की : व्हाट्सऐप

मास्को/एपी। रूस ने देश में व्हाट्सएप पर पूरी तरह से रोक लगाने का प्रयास किया है। सोशल मीडिया कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह इंटरनेट पर नियंत्रण कड़ा करने के सरकार का नया प्रयास है। व्हाट्सएप के एक प्रवक्ता ने बुधवार देर रात बताया कि रूसी अधिकारियों की यह कार्रवाई 'उपयोगकर्ताओं को सरकारी स्वामित्व के निगरानी वाले ऐप की ओर धकेलने' के उद्देश्य से की गई है। यह रूसी सरकारी समर्थित 'मैक्स' मैसेजिंग ऐप की ओर इशारा है, जिसे आलोचक एक निगरानी उपकरण मानते हैं। व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने बताया, यह 10 करोड़ से अधिक लोगों को निजी और सुरक्षित संचार से अलग करने का प्रयास है और इससे रूस में लोगों की सुरक्षा में ही कमी आएगी। हम लोगों को आपस में जोड़े रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

भारतीय वायुसेना ब्रिटिश शाही सेना के पायलटों को प्रशिक्षित करेगी

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय वायुसेना पहली बार ब्रिटेन की शाही वायुसेना के पायलटों को प्रशिक्षण देने जा रही है। यह निर्णय बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में आयोजित 19वीं ब्रिटेन-भारत वायुसेना वार्ता में लिया गया। ब्रिटेन द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, ''नवीनतम समझौते के तहत, भारतीय वायुसेना तीन योग्य उड़ान प्रशिक्षकों (क्यूएफआई) को ब्रिटेन में शाही वायुसेना (आरएएफ) वैली में तैनात करेगी - जो ब्रिटिश लड़ाकू विमानों के पायलटों के लिए प्रशिक्षण केंद्र है।'' इसमें कहा गया, ''यह पहली बार है कि भारतीय योग्य उड़ान प्रशिक्षक आरएएफ वैली में ब्रिटिश पायलटों को लड़ाकू विमानों का प्रशिक्षण देंगे। यह तैनाती शुरू में दो साल की अवधि के लिए होगी।''

नेतन्याहू के साथ मुलाकात में ट्रंप ने ईरान से बातचीत जारी रखने पर दिया जोर

वाशिंगटन/एपी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और ईरान के साथ बातचीत जारी रखने पर जोर दिया। अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते को आगे बढ़ाना चाहता है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच यह मुलाकात 'व्हाइट हाउस' (अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) में हुई।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ''यह मुलाकात बहुत अच्छी रही और दोनों देशों के बीच शानदार रिश्ते जारी रहेंगे।''

स्टालिन ने अर्थव्यवस्था का खाका किया पेश

राष्ट्रीय औसत से तेज तमिलनाडु की वृद्धि : स्टालिन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य की आर्थिक वृद्धि दर 11.19 प्रतिशत के साथ राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक रही है। उन्होंने कहा, आज तमिलनाडु की आर्थिक वृद्धि राष्ट्रीय औसत से अधिक 11.19 प्रतिशत है। स्पष्ट रूप से कहें तो पिछले साल भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 4.5 प्रतिशत रही जबकि तमिलनाडु की वृद्धि इससे तीन गुना 14.7 प्रतिशत रही।

'कन्वर्जन कॉन्क्लेव 2026' को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि यह द्रविड़ मॉडल शासन की आलोचना करने वालों को उनके काम के जरिये दिया गया ''जवाब'' है। यह शिखर सम्मेलन निवेश समझौतों को क्रियान्वित परियोजनाओं में बदलने की प्रक्रिया को दर्शाने की एक अनूठी पहल है। उन्होंने कहा, ''केवल इस सम्मेलन में ही हम 52 कंपनियों के उद्घाटन, 71 कंपनियों के शिलान्यास और दो नई कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) के जरिये उपलब्धियों का उत्सव मना रहे हैं।'' मुख्यमंत्री ने राज्य की औद्योगिक क्षमता का उल्लेख किया और बदलाव लाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक बार एमओयू पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद, उसकी प्रगति पर समर्पित डैशबोर्ड' के जरिये नजर रखी जाती है। स्टालिन के साथ कार्यक्रम में उद्योग मंत्री टी. आर. बी. राजा भी मौजूद रहे।

उन्होंने कागजों पर हस्ताक्षर से वास्तविक परिणाम तक सरकार के बदलाव का विस्तार से उल्लेख किया और कहा कि यह सम्मेलन तमिलनाडु द्वारा अपनाई गई ''इंक टू इम्पैक्ट'' सोच का उत्सव है। उन्होंने कहा, ''किसी अन्य राज्य में एमओयू को वास्तविक निवेश में बदलने को साबित करने के लिए 'कन्वर्जन कॉन्क्लेव' आयोजित करने का न तो साहस है और न ही क्षमता।'' उन्होंने कहा कि सरकार केवल निवेश की मात्रा पर नहीं, बल्कि नौकरियों की संख्या, गुणवत्ता एवं स्थान पर ध्यान देती है।

श्रमिक संगठनों की एक दिन की हड़ताल का सामान्य जनजीवन पर सीमित असर

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के संयुक्त मंच की सरकार की कथित '' मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक नीतियों'' के खिलाफ बृहस्पतिवार को आहूत एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का सामान्य जनजीवन पर कुल मिलाकर अधिक असर नहीं पड़ा।

श्रमिक संगठनों ने कई राज्यों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। कुछ जगहों पर श्रमिक हड़ताल में समर्थन दिखाने के लिए कार्यस्थल पर देर से पहुंचे।

खबरों के मुताबिक ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, गोवा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब सहित कई राज्यों में इसका मिला-जुला असर देखने को मिला। 12 घंटे के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के कारण ओडिशा में सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा।

श्रमिक संगठनों ने दावा किया कि 'यह केंद्रीय सरकार की आम-जन और राष्ट्र-विरोधी नीतियों के खिलाफ बड़ी प्रतिक्रिया' है।

भाजपा-राजग को बड़ी उम्मीद से देख रहा केरल : प्रधानमंत्री मोदी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि केरल सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और विपक्षी एकीकृत लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) से तंग आ चुका है और इस बात पर जोर दिया कि राज्य अब भाजपा-राजग को बड़ी उम्मीद से देख रहा है। मोदी ने यहां तिरुवनंतपुरम नगर निगम के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नवनिर्वाचित पार्षदों और केरल के अन्य नगर निकायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद यह टिप्पणी की।

प्रधानमंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में उनके साथ अपनी बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए कहा, ''सात, लोक कल्याण मार्ग पर केरल भाजपा के पंचायत सदस्यों, नगर पालिका सदस्यों और तिरुवनंतपुरम नगर निगम सहित पूरे केरल के निगमों के सदस्यों की मेजबानी की। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भाजपा को ऐतिहासिक जनादेश मिला था।

मोदी ने कहा कि उन्होंने उनके साथ कई विषयों पर ''विशेष रूप से लोगों के साथ भाजपा के जुड़ाव को गहरा करने, हमारे सुशासन के एजेंडे को आगे बढ़ाने और 'जीवन को आसान बनाने' के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि केरल एलडीएफ और यूडीएफ से ''तंग'' आ गया है और भाजपा-राजग को ''बड़ी उम्मीद'' से देख रहा है। उन्होंने कहा, इसलिए, भारतीय जनता पार्टी-राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के निर्वाचित सदस्य जमीनी स्तर पर काम करेंगे और लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल भाजपा के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बैठक में उन्होंने हर उस कार्यकर्ता को याद किया, जिन्होंने वर्षों से पार्टी को खड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा, ''यह उनके निस्वार्थ प्रयासों के कारण है कि हम राज्य भर में आगे बढ़े हैं। आने वाले समय में, भाजपा केरल में और भी आगे बढ़ेगी।

बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

तिरुवनंतपुरम नगर निगम के भाजपा पार्षद, मेयर वी वी राजेश, और केरल के अन्य नगर निकायों के प्रतिनिधि तीन दिवसीय प्रशासनिक और शासन कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बुधवार को यहां पहुंचे।

भाजपा की केरल इकाई के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि केरल के निर्वाचित प्रतिनिधि प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के बाद उत्साहित और प्रेरित महसूस कर रहे।

केरल के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत के वीडियो फुटेज को साझा करते हुए भाजपा ने 'एक्स' पर लिखा, जब भगवा लहर वास्तविक शासन से मिलती है।

भारत ने 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी

नई दिल्ली/भाषा। रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद के काफी समय से लंबित प्रस्ताव को बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी। आधिकारिक बयान के अनुसार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने सशस्त्र बलों की युद्धक तैयारी को मजबूत करने के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों की पूंजीगत खरीद को मंजूरी दी। सूत्रों ने बताया कि इस परियोजना के तहत, राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन द्वारा 18 विमान सीधे 'उड़ान भरने की स्थिति' में आपूर्ति किए जाएंगे और शेष विमानों का निर्माण भारत में किया जायेगा, जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी उत्पादन शामिल होगा और यह उत्पादन चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। रक्षा मंत्रालय ने खरीद की लागत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अनुमान है कि यह 2.90 लाख करोड़ रुपए से 3.15 लाख करोड़ रुपए के बीच होगी। राफेल विमानों की खरीद को मंजूरी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्रा से ठीक चार दिन पहले मिली।

मुझ पर मुकदमा हो या विशेषाधिकार हनन, किसानों के लिए लड़ूंगा : राहुल

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर देश और किसानों को अमेरिका के हाथों बेचने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार उनके खिलाफ चाहे मुकदमा दर्ज करवाए या विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाए, वह किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी ने 'एक्स' और अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा, ''प्राथमिकी हो, मुकदमा दर्ज हो या विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएं, मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। कोई भी ऐसा व्यापार समझौता जो किसानों की रोज़ी-रोटी छीने या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे, वह किसान-विरोधी है। किसान-विरोधी मोदी सरकार को अन्नदाताओं के हितों से समझौता नहीं करने देंगे।''

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ''किसान विरोधी नरेन्द्र मोदी ने देश के अन्नदाताओं को, उनके खून-पसीने को ट्रम्प (अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप) के हाथों बेच दिया है। आखिर क्यों वह हमेशा किसानों की ही कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं?'' उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री पहले अपने अरबपति मित्रों के मुनाफ़े के लिए काले क़ानून लाए थे, अब ''अपने गले से अमेरिकी शिकंजा हटाने'' के लिए ट्रम्प के अमेरिका के सामने भारतीय खेती के दरवाज़े खोल दिए।

बांग्लादेश में आम चुनाव के बाद मतगणना शुरू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

ढाका/भाषा। बांग्लादेश में महत्वपूर्ण आम चुनाव के लिए बृहस्पतिवार मतदान के बाद मतगणना शुरू हो गई है। नई सरकार अंतरिम प्रशासन की जगह लेगी, जिसने अगस्त 2024 में अवामी लीग शासन के सत्ता से बेदखल होने के बाद कार्यभार संभाला था। बांग्लादेश में जटिल 84 सूत्री सुधार पैकेज पर जनमत संग्रह के साथ-साथ 13वां आम चुनाव कराया गया है। देश भर में 300 में से 299 संसदीय सीट पर मतदान सुबह साढ़े सात बजे (स्थानीय समयानुसार) शुरू हुआ और शाम साढ़े चार बजे तक जारी रहा। हालांकि, जिन जगहों पर मतदाता मतदान केंद्र के अंदर थे, वहां उनके मतदान करने तक मतदान जारी रहा।

एक उम्मीदवार की मृत्यु होने के कारण एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान रद्द कर दिया गया है।

निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा, पहला महत्वपूर्ण परिणाम देर रात तक उपलब्ध हो सकता है।

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अब भंग हो चुकी अवामी लीग की गैरमौजूदगी में मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और उसकी पूर्व सहयोगी जमात-ए-इस्लामी के बीच है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की अवामी लीग को पिछले साल भंग कर दिया था और पार्टी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। देश भर में 299 निर्वाचन क्षेत्रों में 42,779 मतदान केंद्रों पर लगभग 12.7 करोड़ मतदाता अपने मत डालने के लिए पंजीकृत थे। इनमें से 50 लाख पहली बार के मतदाता हैं।

सरकारी 'बीएसएस' समाचार एजेंसी के अनुसार बांग्लादेश निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमद ने बताया कि दोपहर दो बजे तक 48 प्रतिशत मतदान हुआ।

हसीना ने बांग्लादेश चुनावों को 'सुनियोजित नाटक' करार दिया

नई दिल्ली/ढाका/भाषा। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बृहस्पतिवार को अंतरिम सरकार द्वारा कराये जा रहे आम चुनावों को ''एक सुनियोजित नाटक'' करार दिया और ''एक तटस्थ कार्यवाहक सरकार के तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव'' कराने की मांग की। तीस वर्षों में पहली बार, आवामी लीग का चुनावी चिह्न 'नाव' चुनाव के मतपत्र पर दिखाई नहीं दिया, जो अगस्त 2024 में व्यापक राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों में हसीना को सत्ता से हटाने के बाद पहला चुनाव है। भारत में रह रही 78 वर्षीय हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के तहत हो रहे चुनाव मूल रूप से ''एक सुनियोजित नाटक'' हैं।

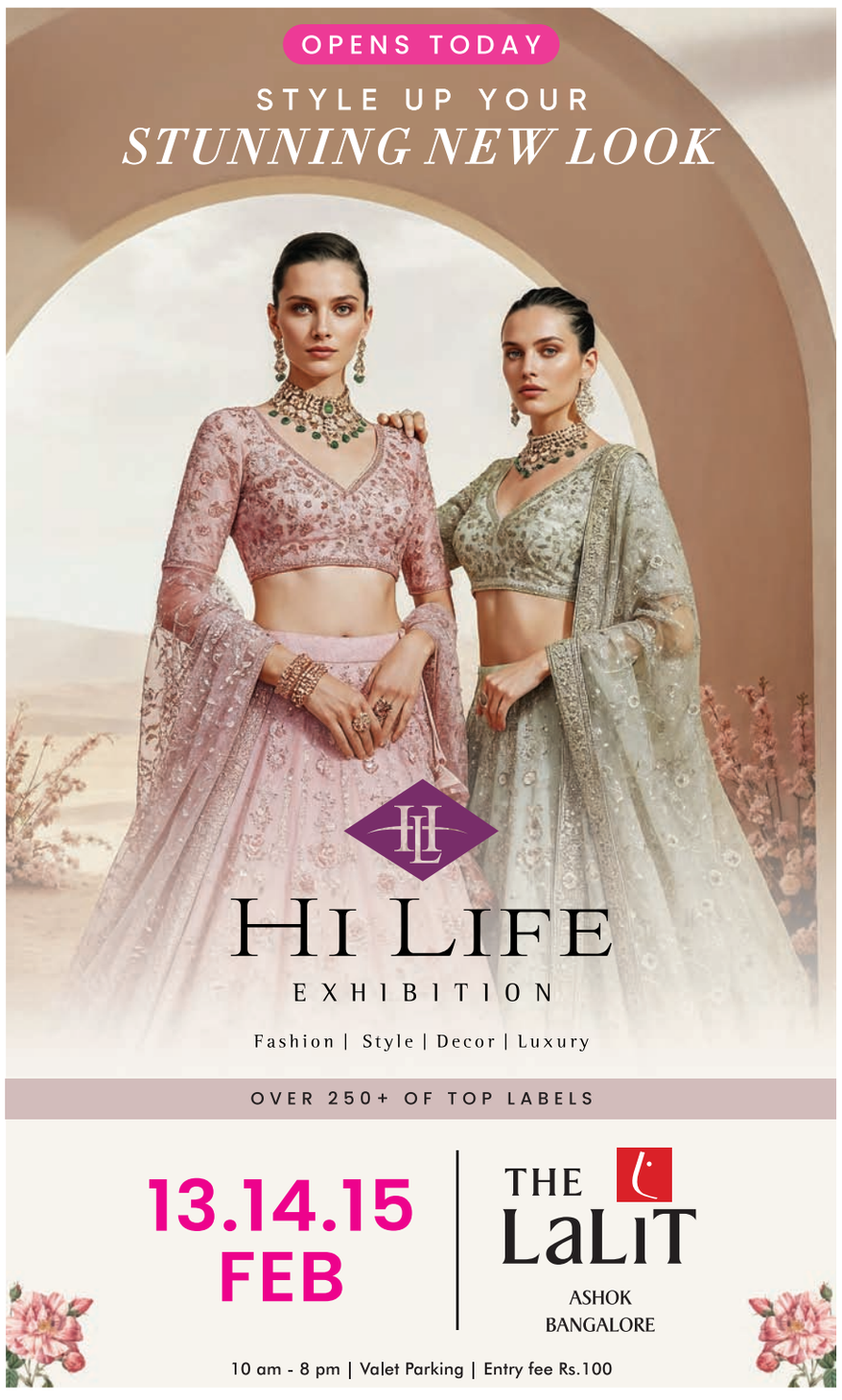

13-02-2026 सूर्यास्त 6:24 बजे | 14-02-2026 सूर्योदय 6:42 बजे

BSE 83,674.92 (-558.72) | NSE 25,807.20 (-146.65)

सोना 16,310 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम | चांदी 260,071 रु. प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

दल-सार

राजनीति में सब दल का,
लगभग समान होता चरित्र।
सत्ता लोभी कुर्सी जुगाड़,
अवसरवादी हैं सभी मित्र।
नायक हैं जिनके दूध धुले,
जनहितकारी सच्चे पवित्र।
सबकी आदर्श संहिताएं,
जिनमें होते हैं कई छिद्र।।

'अर्थव्यवस्था को कमजोर बताने वाले लोग देश की उपलब्धियों का मजाक बना रहे हैं'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि वैश्विक स्थिति के विपरीत भारत में जीडीपी विकास दर अधिक और मुद्रास्फीति कम है जो एक दुर्लभ स्थिति है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर बताने वाले दरअसल देश के उन सभी लोगों का मजाक बना रहे हैं जिनके कारण यह उपलब्धि हासिल हो पायी है।

उच्च सदन में आम बजट 2026-27 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट ऐसे ऐतिहासिक समय में पेश किया जा रहा है जब देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की ऊंची दर है और मुद्रास्फीति की दर कम है जो दुर्लभ बात है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति कोई तुक्का नहीं है बल्कि यह समय पर लिए गए विस्तृत निर्णय एवं कदमों तथा सतत विकास का परिणाम है। उन्होंने कहा, ''यह एक दुर्लभ क्षण है जिसने हमें अगले दो दशक, 2047 तक के लिए योजना बनाने का अवसर दिया है...हमारा लक्ष्य विकसित भारत है।'' इसी पृष्ठभूमि में बजट तैयार किया गया है।

सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2025-26 की वास्तविक जीडीपी विकास दर 7.4 प्रतिशत बतायी गई है तथा सामान्य विकास दर करीब आठ प्रतिशत होगी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक घटकर करीब दो प्रतिशत रह गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि वह जिस स्थिति की बात कर रही है उसमें ऊंची विकास दर, दामों में स्थिरता है जो वैश्विक स्तर पर कम देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत स्थिति को परिलक्षित करती है।

सीतारमण ने कहा कि वह इस बात को दोहराना चाहती हैं कि यह उपलब्धि भारत के लोगों की उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्था बताने वाले और इसकी आलोचना करने वाले लोग दरअसल यह कहकर भारत के उन लोगों की उपलब्धि

का मजाक बना रहे हैं जो अपने-अपने स्तर पर इसके विकास में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2026-27 का बजट इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इन उपलब्धियों का लाभ उठाया जा सके, इन सूक्ष्म आर्थिक स्थिरता कारकों को दीर्घकालिक उत्पादक क्षमताओं में परिवर्तित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस विकास गति को अगले दशकों तक विस्तार दिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इन सबमें आत्मनिर्भरता एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है तथा सरकार ने बजट में जो भी घोषणाएं कीं और नीतियां बनायी हैं, उसमें आत्मनिर्भरता का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा, ''हमने घरेलू उत्पादन क्षमता का निर्माण किया है... बजट का निर्माण करते समय हमने ऊर्जा सुरक्षा को भी अपने ध्यान में रखा है।'' वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस बात को भी ध्यान में रखा कि भारत के लोग भी अपने-अपने क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने कहा कि इसके लिए जीवनयापन की सरलता, रोजगार सृजन में सहयोग, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, परिवारों की क्रय शक्ति को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वो जमाना चला गया जब दिल्ली से एक रूपया चलता था तो लोगों के पास पंद्रह पैसा पहुंचता था, अब एक-एक पैसा लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने कि 2014 के बाद से लाभार्थियों के पास प्रत्यक्ष नकदी अंतरण के माध्यम से 48 लाख करोड़ रुपए पहुंचाया जा चुका है तथा इसके माध्यम से 4.31 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाया गया है।

बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा इस बजट में पुरानी बातों और घोषणाओं को भुला दिए जाने के आरोप का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विगत को कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि उज्ज्वल विगत है तो उसकी सदैव सराहना की जानी चाहिए किंतु यदि वह दागदार हो तो उसकी नकल नहीं की जानी चाहिए। सीतारमण ने कहा कि इस बजट में दहाई अंकों की मुद्रास्फीति, 'पांच कमजोर अर्थव्यवस्था', फोन कॉल पर बैंकों से कर्ज देने के लिए कहा जाने, ऊंचे घाटे, घटते अवसर आदि पूर्व सरकार के शासनकाल की बातों को याद रखा गया है। उन्होंने कहा कि पहले नारा हुआ करता था, ''रोजगार विहीन विकास।'' उन्होंने कहा, ''मैं इसे कभी नहीं भूलती हूं किंतु उससे सीखती हूं।''

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि उच्च आयकर संग्रह का यह अर्थ नहीं है कि देश में मध्यम वर्ग का दमन हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश में मध्यम वर्ग के दमन का कोई सबूत नहीं है, बल्कि मध्यम वर्ग के विस्तार के सबूत जरूर हैं। उन्होंने कहा, उच्च व्यक्तिगत आयकर संग्रह का यह अर्थ नहीं है कि देश में मध्यम वर्ग का दमन हो रहा है।

अहमदाबाद के एक व्यावसायिक परिसर में आग लगी, 100 लोगों को बचाया गया, कोई हताहत नहीं

अहमदाबाद/भाषा। गुजरात के अहमदाबाद में 11 मंजिला एक कार्यालय परिसर में आग लगने के बाद कम से कम 100 लोगों को बचा लिया गया। इस हादसे में हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वस्त्रपुर इलाके में आईटीसी नर्मदा होटल के निकट 'शिवालिक हाईस्ट्रीट' इमारत की चौथी मंजिल पर एक रियल एस्टेट कार्यालय में आग लगने के बाद व्यावसायिक परिसर में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी अमित डोंगरे ने कहा कि अहमदाबाद अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के कर्मियों द्वारा चलाये गए एक घंटे के अभियान में कम से कम 100 लोगों को बचाया गया। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कुल 13 गाड़ियों को भेजा गया। आग लगने के कारण का तत्काल पता नहीं चल सका है। अधिकारियों ने बताया कि सीढ़ियों में धुआं भर जाने के बाद लोग इमारत की छत पर जाने लगे। दमकल विभाग द्वारा साझा किए गए दृश्यों में दिखाया गया है कि रियल एस्टेट कार्यालय पूरी तरह से जलकर खाक हो गया।

प्रतिस्पर्धा आयोग ने इंटेल पर लगाया 27.38 करोड़ रुपए का जुर्माना

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए 'बॉक्स्ड माइक्रो प्रोसेसर' (बीएमपी) के संबंध में भारत के लिए एक अलग वारंटी नीति अपनाने को लेकर अमेरिकी कंपनी इंटेल कॉर्प पर 27.38 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इंटेल अमेरिका की एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय सेमीकंडक्टर कंपनी है, जो कंप्यूटर प्रोसेसर और चिप विनिर्माण के लिए जानी जाती है। आयोग ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि इंटेल ने भारत में बॉक्स्ड माइक्रो प्रोसेसर के बाजार में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग किया है। प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच में पाया गया कि भारत के लिए इंटेल की अलग वारंटी नीति चीन, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में लागू उसकी वारंटी नीतियों की तुलना में भेदभावपूर्ण थी। सीसीआई के अनुसार, अमेरिकी कंपनी की इस नीति ने उपभोक्ताओं और समानांतर आयातकों के विकल्प सीमित करने का काम किया, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। समानांतर आयात का मतलब ऐसे वैध उत्पादों के आयात से है, जो किसी कंपनी के आधिकारिक वितरण चैनल के बाहर से खरीदे जाते हैं। आयोग ने कहा कि डेस्कटॉप कंप्यूटर के बीएमपी पर वारंटी संबंधी इंटेल की यह नीति आठ वर्षों तक लागू रही। इस अवधि को ध्यान में रखते हुए नियामक ने इंटेल के औसत प्रासंगिक कारोबार के आठ प्रतिशत के बराबर जुर्माना निर्धारित किया।

दूध न देने को लेकर हुए विवाद में महिला ने चबाई किसान की उंगली

रायसेन/भाषा। मध्यप्रदेश में रायसेन जिले के एक गांव में बृहस्पतिवार को एक महिला ने एक किसान से पूजा के लिए गाय का दूध मांगा और जब उसने इनकार कर दिया तो तीखी बहस के बाद कथित तौर पर उसकी उंगली चबा ली। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। सलामतपुर थाने के प्रभारी दिनेश रघुवंशी ने बताया कि घटना जिला मुख्यालय से करीब 26 किलोमीटर दूर सलामतपुर थानाक्षेत्र के बांसखेड़ा गांव में हुई। किसान लक्ष्मण सिंह कोरी ने शिकायत में कहा कि उनके पड़ोसी महाराज सिंह कोरी की पत्नी माया बाई कोरी सुबह गाय का दूध मांगने के लिए उनके घर आई थी और जब उसने मना कर दिया तो दोनों के बीच बहस हो गई एवं महिला ने कथित तौर पर उसे गाली देना शुरू कर दिया। झगड़े के दौरान महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी एक उंगली अपने मुंह में डाल ली और उसे चबा लिया। रघुवंशी ने बताया कि घायल किसान की मेडिकल जांच की गई और महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला माया बाई ने अपने बयान में बताया कि वह हर बृहस्पतिवार को व्रत रखती है और पीले वस्त्र धारण कर गाय का दूध, पीले फल-फूल, चने की दाल एवं गुड़ से भगवान विष्णु की पूजा करती है।

अंतरराज्यीय हेरोइन तस्करी की प्रमुख गिरफ्तार, पूरा परिवार तस्करी में शामिल

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सक्रिय एक अंतरराज्यीय हेरोइन तस्करी गिरोह की कथित प्रमुख कड़ी और मादक पदार्थों की तस्करी से लंबे समय से जुड़े एक परिवार की सदस्य 40-वर्षीय महिला को पूर्वी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी सपना राही को 10 फरवरी को शाहदरा इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, वह मादक पदार्थ गिरोह में एक प्रमुख तस्कर के रूप में काम करती थी और सह-आरोपी बबीता को हेरोइन की कथित तौर पर आपूर्ति करती थी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, सपना, सुरेश राही की बेटी है, जो कथित तौर पर मादक पदार्थ तस्कर है और उसपर स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सपना की मां और भाइयों पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अधिकारी ने बताया कि उनमें से कुछ वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस ने बताया कि यह परिवार पूर्वी दिल्ली के यमुना पार इलाके में एक संगठित मादक पदार्थ गिरोह चला रहा था। पुलिस के अनुसार, सपना की गिरफ्तारी इसी मामले में शाहदरा निवासी बबीता (46) और सुल्तानपुरी निवासी संध्या (36) की गिरफ्तारी के बाद हुई है।

किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाने के लिए आरबीआई ने जारी किया मसौदा संशोधन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन और एकीकरण के लिए बृहस्पतिवार को मसौदा जारी किया जिसका उद्देश्य कवरेज का विस्तार, परिचालन प्रक्रियाओं का सरलीकरण और कृषि क्षेत्र की उभरती जरूरतों का ध्यान रखना है।

केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि विनियमित संस्थाएं, आम लोग और अन्य हितधारक छह मार्च, 2026 तक मसौदे पर टिप्पणियां और सुझाव दे सकते हैं। आरबीआई ने केसीसी ऋण की स्वीकृति और पुनर्भुगतान कार्यक्रम में एकरूपता लाने के लिए फसल सत्रों की अवधि को मानकीकृत करने का प्रस्ताव भी रखा है। इसके तहत कम अवधि में तैयार होने वाली फसलों को 12 माह के चक्र और लंबी अवधि वाली फसलों को 18 माह के चक्र के रूप में परिभाषित किया गया है। लंबी अवधि की फसलों के चक्र के अनुरूप ऋण अवधि तय करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की कुल अवधि छह वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है। मसौदे में केसीसी के तहत निकासी सीमा को प्रत्येक फसल सत्र के लिए फसल की अनुमानित लागत के साथ समायोजित करने का सुझाव दिया गया है, ताकि किसानों को वास्तविक खेती लागत के अनुरूप पर्याप्त ऋण मिल सके। इसके अलावा, मिट्टी की जांच, वास्तविक समय में मौसम पूर्वानुमान और जैविक एवं उत्तम कृषि पद्धतियों के प्रमाणन जैसे तकनीकी खर्चों को भी पात्र मद में शामिल किया गया है। ये खर्च कृषि परिसंपत्तियों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए वर्तमान में स्वीकृत 20 प्रतिशत अतिरिक्त घटक के भीतर रखे जाएंगे। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने फरवरी के मौद्रिक नीतिगत वक्तव्य में केसीसी से संबंधित इन संशोधनों की घोषणा की थी।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने चार हवाई अड्डों के लिए केंद्र से मंजूरी मांगी

नई दिल्ली/भाषा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी में नागर विमानन, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य के चार हवाई अड्डों सहित विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए केंद्र से सहायता की मांग की।

नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू के साथ बैठक में रेड्डी ने केंद्र से वारंगल के पास स्थित ममनूर हवाई अड्डे पर काम शुरू करने का आग्रह किया और कहा कि परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित कोठागुडेम हवाई अड्डे के लिए 'आब्स्टकल लिमिटेशन सर्फेस (ओएलएस)' सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन का भी अनुरोध किया, जिसके लिए पलवंचा में भूमि की पहचान की गई है।

सेबी विनियमन की लागत कम करने के लिए विभिन्न उपायों पर दे रहा ध्यान : पांडेय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने बृहस्पतिवार को कहा कि पूंजी बाजार नियामक विभिन्न उपायों के जरिये विनियमन की लागत कम करने पर विचार कर रहा है। उन्होंने बताया कि इन प्रयासों में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन शामिल है, जो नियामकीय कदमों के प्रभाव का आकलन करेगी। इसके अलावा, राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम) में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा नियामकीय अध्ययन केंद्र भी इस दिशा में काम कर रहा है।

पांडेय ने कहा कि सेबी का आर्थिक और नीति विश्लेषण विभाग

(डीईपीए) इस मामले में काम कर रहा है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के प्रमुख ने इस विषय को अभी शुरुआती चरण में बताते हुए कहा कि नियामकीय प्रभाव आकलन करने की आवश्यकता है, जिसमें उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नीतिगत परिणामों का अध्ययन शामिल होगा। पांडेय ने कहा, ''हमारे सभी उपायों की लागत-दक्षता महत्वपूर्ण है।'' उन्होंने कहा कि अधिक लागत हमें गैर-प्रतिस्पर्धी बना सकती है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ समय पहले इस तरह के प्रयास शुरू करने का जिक्र किया था। यह पूछे जाने पर कि क्या रिजर्व बैंक ने भी इसे प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया है और क्या वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) ने इस पर चर्चा की है, तो उन्होंने इसका सकारात्मक जवाब दिया।

पांडेय ने कहा कि सेबी का दृष्टिकोण बाजार की अखंडता और निवेशक संरक्षण के प्रति सतर्क रहते हुए नवाचार को प्रोत्साहित करना रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि नवाचार जोखिम रहित नहीं हो सकता।

उन्होंने कहा कि पूंजी बाजार के नजरिये से कृत्रिम मेधा से उत्पन्न जोखिमों का अध्ययन करने की भी आवश्यकता है और शोधकर्ताओं से नियामक निकायों के साथ साझेदारी करने का आग्रह किया।

सरकार ने नई सीपीआई श्रृंखला जारी की, जनवरी में खुदरा मुद्रास्फीति 2.75 प्रतिशत

नई दिल्ली/भाषा। वर्ष 2024 को आधार वर्ष मानते हुए जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की नई श्रृंखला के तहत जनवरी में खुदरा मुद्रास्फीति 2.75 प्रतिशत रही है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी की गई नई श्रृंखला में वस्तुओं की संख्या 259 से बढ़ाकर 308 और सेवाओं की संख्या 40 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है, ताकि मूल्य स्थिति की बेहतर तस्वीर पेश की जा सके।

खाद्य मुद्रास्फीति जनवरी में 2.13 प्रतिशत और आवासीय मुद्रास्फीति 2.05 प्रतिशत रही।

वर्ष 2012 को आधार वर्ष मानने वाली पुरानी श्रृंखला के तहत जनवरी, 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.26 प्रतिशत जबकि दिसंबर में 1.33 प्रतिशत रही थी। एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल मुद्रास्फीति दर 2.73 प्रतिशत और शहरी भारत में 2.77 प्रतिशत रही। नई सीपीआई श्रृंखला के अनुसार, तेलंगाना में महंगाई दर सबसे अधिक 4.92 प्रतिशत रही। इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान रहा। आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में सबसे कम महंगाई वाली शीर्ष पांच वस्तुएं लहसुन, प्याज, आलू, अरहर, तुअर दाल और मटर रहीं। दूसरी ओर चांदी के आभूषण, टमाटर, नारियल खोपरा, सोना, हीरा, प्लैटिनम के आभूषण और नारियल तेल महंगे हुए।

देश में डिजिटल भुगतान का प्रसार पहली छमाही में भी जारी रहा: आरबीआई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश में डिजिटल भुगतान का दायरा बढ़ने का सिलसिला अप्रैल-सितंबर, 2025 के दौरान भी जारी रहा।

आरबीआई ने कहा कि उसका 'डिजिटल भुगतान सूचकांक' (आरबीआई-डीपीआई) सितंबर, 2025 में 516.76 पर पहुंच गया, जो सितंबर, 2024 में 465.33 और मार्च, 2025 में 493.22 पर था। देशभर में डिजिटल भुगतान के प्रसार और दायरे को मापने वाला यह सूचकांक जनवरी, 2021 से प्रकाशित किया जा रहा है और मार्च, 2018 को आधार वर्ष मानता है। आरबीआई ने बयान में कहा, ''सूचकांक में वृद्धि का मुख्य कारण भुगतान प्रदर्शन और भुगतान सक्षम कारकों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी है।'' आरबीआई-डीपीआई पांच प्रमुख मानकों पर आधारित है। इसमें भुगतान सक्षम कारक (25 प्रतिशत भार), मांग पक्ष का भुगतान ढांचा (10 प्रतिशत), आपूर्ति पक्ष का भुगतान ढांचा (15 प्रतिशत), भुगतान प्रदर्शन (45 प्रतिशत) और उपभोक्ता केंद्रीकरण (पांच प्रतिशत) शामिल हैं।

इन सभी मानकों के कई उप-मानक और मापनीय संकेतक रखे गए हैं, जिनके आधार पर समय-समय पर डिजिटल भुगतान की प्रगति का आकलन किया जाता है।

नई सीपीआई आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार करेगी : सीईए नागेश्वरन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने बृहस्पतिवार को कहा कि नई अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) श्रृंखला मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों को तैयार करने में उपयोग किए जाने वाले आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार करेगी।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने बृहस्पतिवार को नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) जारी किया।

नई श्रृंखला में अधिक वस्तुएं और सेवाएं शामिल की गई हैं, जबकि वे वस्तुएं हटा दी गई हैं जिनका वर्तमान समय में उपयोग नहीं हो रहा है।

नागेश्वरन ने नई सीपीआई श्रृंखला पर एक संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा, ''चूंकि अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) का सामान और सेवाओं का समूह हाल के व्यय आंकड़ों के अनुरूप है, इसलिए इससे जो महंगाई के संकेत मिलेंगे वे आर्थिक परिस्थितियों के और अधिक करीब होंगे। इससे मौद्रिक और राजकोषीय नीति को समायोजित करने के लिए सूचना आधार में सुधार होगा।'' उन्होंने कहा कि नई सीपीआई श्रृंखला, जिसमें सेवाओं और डिजिटल बाजारों का व्यापक समावेश है, नीति निर्माताओं को वास्तविक आय, उपभोग के रुझान और खरीद क्षमता का आकलन करने के लिए अधिक सटीक और ताजा आधार प्रदान करती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्विमासिक मौद्रिक नीति निर्णय लेते समय खुदरा मुद्रास्फीति को ध्यान में रखता है। उन्होंने कहा कि यदि सीपीआई में उतार-चढ़ाव कम हो जाता है, तो उससे जुड़े राजकोषीय व्यय खर्च, महंगाई भत्ता (डीए) तय करना और इंडेक्स बॉन्ड अधिक स्थिर और भरोसेमंद हो जाएंगे।

मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि नई श्रृंखला में खाद्य समूह का भारांश 2012 की सीपीआई में 45.86 प्रतिशत से घटकर 36.75 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने कहा कि यह रेस्तरां और सेवाओं जैसी अन्य श्रेणियों में कुछ वस्तुओं के पुनः आवंटन को भी दर्शाता है।

नागेश्वरन ने कहा, ''आर्थिक दृष्टि से यह स्वास्थ्य, शिक्षा, आवागमन और संपर्क जैसे क्षेत्रों में खर्च में विविधता को दर्शाता है, जो एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था में देखा जाता है, जहां आय और जीवन स्तर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य और पेय पदार्थों के समूह का कम भार मुख्य महंगाई दर को भी कम अस्थिर बना सकता है। उन्होंने कहा, इस तरह का पुनर्संतुलन आम तौर पर आय वृद्धि, उत्पादकता लाभ और जीवन स्तर में सुधार से जुड़ा होता है।

नागेश्वरन ने कहा कि संशोधित सूची में यह दिखाया गया है कि उपभोग में सेवाओं की भूमिका बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा, ''यह उपभोग माप को उत्पादन और रोजगार की उभरती संरचना के करीब लाता है, जहां सेवाएं आर्थिक गतिविधियों की बढ़ती हिस्सेदारी के लिए जिम्मेदार हैं।

नागेश्वरन ने कहा कि नई श्रृंखला कीमतों के निर्धारण में डिजिटल माध्यम की बढ़ती भूमिका को भी मानती है और इससे राज्यों में महंगाई के शहरी और ग्रामीण स्वरूप को साथ ही विभिन्न उप-श्रेणियों और वस्तुओं के स्तर पर बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी।

औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक लोस में पारित, सरकार ने कहा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन की गारंटी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। लोकसभा ने बृहस्पतिवार को 'औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026' को पारित कर दिया और सरकार ने संहिता के संबंध में विपक्ष की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि यह श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की गारंटी देती है।

केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा, ''इस श्रम संहिता में हमने सुनिश्चित किया है कि संवैधानिक सुरक्षा मानकों के साथ न्यूनतम वेतन मानक तय करेंगे। देश में महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन पाने का अधिकार होगा।''

मंत्री ने कहा कि औद्योगिक संबंध संहिता तो 2020 में ही पारित हो चुकी है और ढाई महीने पहले लागू भी हो चुकी है, लेकिन अधिकतर सदस्यों ने चर्चा में संहिता की ही बात की है और इसे कामगार विरोधी बताया है। मांडविया ने कहा, ''हम तो एक छोटा सा संशोधन लाए हैं। यह संशोधन केवल कानूनी स्पष्टता के लिए सदन में लाया गया।'' उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। औद्योगिक सबंध संहिता, 2020 ने जिन कानूनों की जगह ली है, उनमें ट्रेड यूनियन्स अधिनियम, 1926, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 शामिल हैं, जो श्रमिक संघों, औद्योगिक रोजगार और औद्योगिक विवादों से संबंधित हैं।

मांडविया ने कहा, ''हम श्रमिकों के हित में एक संहिता लाए। तीन कानूनों को इसमें शामिल किया गया। उन्हें निरस्त करने का अधिकार सरकार को है और निरस्त कर दिया गया है, लेकिन कानून में भी यह बात शामिल हो, इसलिए संशोधन विधेयक लाया गया।'' संहिता के विरोध में देशभर में हड़ताल को लेकर विपक्ष के कुछ सदस्यों की टिप्पणियों पर मंत्री ने कहा, ''चंद श्रमिक संगठनों ने विरोध किया होगा, 17 राष्ट्रीय संगठनों ने तो बंद को अनुचित बताया है। श्रमिकों के हित में यह संहिता लाई गई है।'' उन्होंने कहा कि विपक्ष ने भी बंद की हकीकत देखी होगी। उन्होंने कहा, ''देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सच के साथ रहेगा। आपकी (विपक्ष की) बात सच होती तो देश सड़क पर होता।'' मांडविया ने आरएसपी सांसद एन के प्रेमचंद्रन के आरोपों का उल्लेख करते हुए कहा कि वामपंथी दलों के सदस्यों ने इस संहिता के खिलाफ जोर-शोर से बात रखी है।

दूध न देने को लेकर हुए विवाद में महिला ने चबाई किसान की उंगली

मुंबई/भाषा। मुंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को महानगर में सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमणों पर चिंता व्यक्त करते हुए स्थिति को ''गंभीर'' बताया और टिप्पणी की कि भविष्य में निवासियों को साइकिल और घोड़ों से आने-जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

न्यायमूर्ति रविंद्र घुगे और न्यायमूर्ति अभय मंत्री की पीठ ने चिंता जताई कि यदि अतिक्रमण और अवैध कब्जे बिना किसी रोक-टोक के जारी रहे तो अगले दो दशकों में मुंबई शहर का क्या हाल होगा। उन्होंने स्थानीय नगर निकाय को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि वह बेबस प्रतीत होता है और उसमें अतिक्रमण हटाने का साहस नहीं है। अदालत ने टिप्पणी की, ''यदि इन (अवैध निर्माणों) पर रोक नहीं लगाई गई, तो भविष्य में लोगों को अतिक्रमित सड़कों पर केवल दोपहिया वाहनों, साइकिल या घोड़ों की सवारी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।'' इसने कहा, ''हर जगह सड़कों पर केवल एक या दो लेन बची हैं और फिर यातायात जाम हो जाता है। गाड़ियां चल नहीं पातीं- जाम में फंसी ऐसी गाड़ियों की तुलना में व्यक्ति पैदल ज्यादा तेज चल लेता है।''

अदालत ने ये टिप्पणियां उपनगरीय पवई के एक स्कूल द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान कीं, जिसमें संस्थान के आसपास के अतिक्रमणों के खिलाफ बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की कथित निष्क्रियता पर चिंता जताई गई थी। पीठ ने नगर निकाय अधिकारियों से सवाल किया कि सड़कों पर अनधिकृत निर्माण कैसे किए जा सकते हैं और संबंधित निगम उपायुक्त को शुक्रवार को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। बीएमसी के वकील ने अदालत को बताया कि नगर निकाय ने अतीत में अतिक्रमणकारियों को हटाने का प्रयास किया था, लेकिन वे हिंसक हो गए थे और अधिकारियों को धमकी दी थी।

सेंट्रल ट्रेड यूनियनों और किसान एसोसिएशन के सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जब वे लेबर रिफॉर्म और दूसरी आर्थिक नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें 'मजदूर-विरोधी' बताया जा रहा है।

कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच शिवकुमार ने कहा

'धैर्य का फल मिलेगा'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु/नई दिल्ली। कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने नई दिल्ली में बृहस्पतिवार को कहा कि 'धैर्य का फल मिलेगा'।

सिद्दरामय्या सरकार शुक्रवार को 1,000 दिन पूरे करने जा रही है। शिवकुमार ने मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या के साथ किसी तरह के सत्ता संघर्ष की बात से इनकार किया। इन खबरों पर कि कुछ विधायक 16 फरवरी से तीन मार्च तक विदेश यात्रा पर जा रहे हैं जिसका मकसद मुख्यमंत्री और उनके उपमुख्यमंत्री के बीच सत्ता की साझेदारी में देरी करना है, शिवकुमार ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी भी बात की जानकारी नहीं है।

उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, ''मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैंने इसे सिर्फ अखबारों में पढ़ा है।'' दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ-साथ एआईसीसी

अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात के बाद शिवकुमार ने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर उनसे कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने दोहराया कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व राज्य के हित में उचित समय पर निर्णय लेगा। उन्होंने पत्रकारों से कहा, ''पार्टी नेतृत्व और वरिष्ठ नेता कर्नाटक और पार्टी के हित में जब भी उचित समझेंगे, निर्णय लेंगे।''

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें धैर्य रखने के लिए कहा गया है, तो शिवकुमार ने कहा, ''धैर्य का भी फल मिलेगा।'' उन्होंने पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ हुई बैठक के निष्कर्ष के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया।

लोकायुक्त की छापेमारी में सरकारी अभियंता के मित्र के फ्लैट से 1.70 करोड़ रुपये बरामद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक में आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में लोकायुक्त द्वारा की गई छापेमारी के दौरान एक वरिष्ठ सरकारी अभियंता के मित्र के फ्लैट से 1.70 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। 'यह बरामदगी कर्नाटक रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी के अधीक्षण अभियंता एच एम जनार्दन से जुड़े परिसरों पर की गई तलाशी के दौरान हुई। उनके खिलाफ ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों के संबंध में बेंगलूरु ग्रामीण लोकायुक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।

एक लोकायुक्त अधिकारी ने कहा, 'एच एम जनार्दन के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले के सिलसिले में छह स्थानों पर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उनके मित्र सुजय शेट्टी के फ्लैट से 1.70 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए।' अधिकारी ने बताया कि तलाश अभियान जारी है और अन्य विवरण जुटाए जा रहे हैं। इससे पहले दिन में लोकायुक्त की टीम ने कर्नाटक में चार सरकारी अधिकारियों से जुड़े परिसरों पर एक साथ छापेमारी की। लोकायुक्त के अनुसार, आय से अधिक संपत्ति के मामलों के संबंध में बेंगलूरु, दावणगेरे और धारवाड़ में स्थित संपत्तियों को निशाना बनाया गया। जांच के दायरे में आने वाले अधिकारियों में जनार्दन के अलावा बीईएसकॉम, दावणगेरे में सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल) अर्जुन आर एच भी शामिल हैं।

लोकायुक्त के एक सूत्र ने कहा, तलाश अभियान कथित अनियमितताओं और आय से अधिक संपत्ति की जांच के तहत जारी कार्रवाई का हिस्सा है। संबंधित दस्तावेजों और सामग्रियों की जांच की जा रही है।' मामले में जांच जारी है।

अनधिकृत रूप से विद्यार्थियों को यात्रा पर ले जाने के लिए प्रधानाध्यापक निलंबित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मंगलूरु। दक्षिण कन्नड़ जिले में एक सरकारी स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक को कथित तौर पर अनधिकृत रूप से विद्यार्थियों को यात्रा पर ले जाने को लेकर निलंबित कर दिया गया है। विद्यार्थियों की यात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद यह कार्रवाई की गई। शिक्षा विभाग के सूत्रों ने कहा कि यह घटना नौ फरवरी की है।

उन्होंने कहा कि बेलथांगडी तालुक के बालांजे गांव में राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को कथित तौर पर ऐसे वाहनों में नलकूर के एक निजी फार्म पर ले जाया गया जो स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए अधिकृत नहीं थे। प्रारंभिक जानकारी से संकेत मिलता है कि 3,000 रुपये के किराए पर एक वाहन और एक 'टिपर ट्रक' लिया गया था और इस यात्रा को शैक्षणिक यात्रा बताया गया। इन वाहनों में विद्यार्थियों की यात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद लोगों का ध्यान इस पर गया और जांच शुरू की गई।

बेलथांगडी प्रखंड के शिक्षा अधिकारी ताराकेसरी ने जानकारी एकत्रित करने के लिए बुधवार को स्कूल का दौरा किया और दक्षिण कन्नड़ के सार्वजनिक अनुदेश उप निदेशक (डीडीपीआई) शशिधर जी.एस. को रिपोर्ट सौंपी। अधिकारियों ने कहा कि इस रिपोर्ट के आधार पर डीडीपीआई ने विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक किरण के निलंबन का आदेश पारित किया। प्रधानाध्यापक की जवाबदेही तय करने के लिए जांच शुरू की गई है।

रेपका में हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। यहां यलहंका स्थित रेल पहिया कारखाना (रेपका) में 12 फरवरी को रेपका के प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर व मुख्य राजभाषा अधिकारी आनन्द स्वरूप की अध्यक्षता में दिसंबर-2025 को समाप्त तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी विभागाध्यक्षों ने भाग लिया और हिंदी की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य राजभाषा अधिकारी ने रेल पहिया कारखाना में हिंदी के प्रयोग-प्रसार की सराहना की और अधीनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों को हिंदी में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप काम करने का सुझाव दिया। उन्होंने हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा प्रदान की गई रेल मंत्री राजभाषा ट्रॉफी प्राप्त करने पर रेल पहिया कारखाना के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। राजभाषा अधिकारी एस. सविता ने प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर व मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं सभी विभागाध्यक्षों का स्वागत किया।

बेंगलूरु हवाई अड्डे पर 3.43 करोड़ रुपये का मादक पदार्थ जब्त

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो अलग-अलग मामलों में 3.43 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए और तस्करी के प्रयासों के संबंध में दो यात्रियों को गिरफ्तार किया गया।

बेंगलूरु सीमा शुल्क अधिकारियों ने यह जानकारी दी। विभाग ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में बताया कि पहले मामले में अधिकारियों ने बैंकॉक से आए एक यात्री को रोका और उसके सामान में छिपाया गया 9.7 किलोग्राम 'हाइड्रोपोनिक गांजा' बरामद किया, जिसकी कीमत 3.39 करोड़ रुपये आंकी गई है।

सीमा शुल्क विभाग ने बताया कि उसी दिन एक अन्य मामले में उसने बैंकॉक से आ रहे एक यात्री को रोका और कैंडी के पैकेट में छिपाकर रखी गई 1.7 किलोग्राम हशीश/चरस जब्त की, जिसकी कीमत 4.25 लाख रुपये आंकी गई है। दोनों आरोपियों को स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया।

बीएचईएल में सरकार की पांच प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री को 1.34 गुना अभिदान मिला

बेंगलूरु/नई दिल्ली। खुदरा और संस्थागत निवेशकों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया से भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) में सरकार की पांच प्रतिशत तक हिस्सेदारी की बिक्री पेशकश (ओएफएस) को 1.34 गुना अधिक अभिदान मिला। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) के सचिव अरुणीश चावला ने एक्स पर कहा, ''भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का दूसरा दिन खुदरा निवेशकों की उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया के साथ बंद हुआ। ओएफएस को 1.34 गुना अभिदान मिला।'' बुधवार को संस्थागत निवेशकों ने 256.07 रुपये प्रति शेयर के सांकेतिक मूल्य पर 22.07 करोड़ शेयरों के लिए बोली लगाई थी, जो कुल मिलाकर 5,650 करोड़ रुपये से अधिक थी। सरकार दो दिन की बिक्री पेशकश के तहत 254 रुपये के न्यूनतम मूल्य पर बीएचईएल में तीन प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी बेच रही है। इसमें दो प्रतिशत अतिरिक्त का 'ग्रीनशू' विकल्प भी शामिल है। निर्गम के मूल आकार में बीएचईएल के 10.44 करोड़ से अधिक शेयर या तीन प्रतिशत हिस्सेदारी शामिल है जबकि 'ग्रीनशू' विकल्प के तहत 6.96 करोड़ से अधिक शेयर या दो प्रतिशत हिस्सेदारी बेची जा सकती है।

दक्षिण पश्चिम रेलवे

ई-निविदा सूचना सं. 29-सीडब्ल्यूएस-एमवाईएसएस-2025-26 दिनांक 07.02.2026 का प्रकाशन

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित करते हैं।

कार्य की मद	अनुमानित लागत
आईसीएफ/बीओएक्सएन/बीएलसी/लोको एवं एलएचबी व्हील सेट के कंडेम्ड व्हील डिस्क की ऑक्सी कटिंग।	रू. 10,04,177.64/-

निविदाएँ जमा करने की अंतिम तिथि 02.03.2026 को 15.30 बजे तक

विस्तृत विवरणों के लिए लॉग ऑन करें www.ireps.gov.in

उप मुख्य वर्कशाप प्रबंधक/मैसूर

PUB/893/AAD360/PRB/SWR/2025-26

रेलवन भारतीय रेल का ऑल-इन-वन रेलवे ऐप है। यात्रीगण आरक्षित टिकट, अनारक्षित टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और सीजन पास बुक कर सकते हैं, पीएनआर स्टेटस चेक कर सकते हैं, खाना ऑर्डर कर सकते हैं और कई अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। **रेलवन** ऐप डाउनलोड करें, डिजिटल भुगतान का उपयोग करके अनारक्षित टिकट बुक करें और 3 प्रतिशत तक छूट का लाभ उठाएं।

South Western Railway - SWR SWRRLY SWRRLY

दक्षिण पश्चिम रेलवे

ई-निविदा सूचना सं. एचई-टीआरडी-2025-26-ओटी-38 दिनांक: 06.02.2026

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित करते हैं।

कार्य का नाम	अनुमानित मूल्य
हुब्बल्लि डिविजन के टॉवर वैगनों का 2 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक रखरखाव सहित जरूरी परिवर्तन सामग्री/स्पेयर्स की आपूर्ति और अनुसूचित रखरखाव।	रू. 11,12,11,754.92/-

निविदाएँ जमा करने की अंतिम तिथि 10.03.2026 को 11.00 बजे तक

विस्तृत विवरणों के लिए लॉग ऑन करें www.ireps.gov.in

वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता/टीआरडी/हुब्बल्लि

PUB/892/AAD360/PRB/SWR/2025-26

रेलवन भारतीय रेल का ऑल-इन-वन रेलवे ऐप है। यात्रीगण आरक्षित टिकट, अनारक्षित टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और सीजन पास बुक कर सकते हैं, पीएनआर स्टेटस चेक कर सकते हैं, खाना ऑर्डर कर सकते हैं और कई अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। **रेलवन** ऐप डाउनलोड करें, डिजिटल भुगतान का उपयोग करके अनारक्षित टिकट बुक करें और 3 प्रतिशत तक छूट का लाभ उठाएं।

South Western Railway - SWR SWRRLY @SWRRAILWAYHQ @sw_railways

भारतीय रिज़र्व बैंक

मासंप्रवि-केंद्रीय स्थापना अनुभाग

बेंगलूरू - 560001

भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलुरु के मुख्य कार्यालय परिसर और बेंगलुरु में बैंक की कॉलोनियों के औषधालयों में दवाओं की आपूर्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलुरु शहर के विभिन्न स्थानों पर अपने औषधालयों में दवाओं की आपूर्ति के लिए पात्र आपूर्तिकर्ताओं / स्टॉकिस्टों / दवा-विक्रेताओं से ई-निविदाएं आमंत्रित करता है। निविदा प्रपत्र, विस्तृत नियम और शर्तें दर-सूची के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) दस्तावेज़ में उपलब्ध हैं जिन्हें रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in के निविदा अनुभाग से दिनांक **फरवरी 13, 2026** से डाउनलोड किया /देखा जा सकता है।

निविदा में भाग लेने के लिए आवेदन, निर्धारित प्रारूप में पात्रता मानदंड और मूल्य बोलियों के समर्थन में दस्तावेज एमएसटीसी ई-पोर्टल (वर्सन-3-सामान्य पोर्टल) https://www.mstcecommerce.com/eprocn पर अपलोड किए जाने चाहिए।

दिनांक : 13.02.2026 **क्षेत्रीय निदेशक**
भारतीय रिज़र्व बैंक , बेंगलूरू

उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु/नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के भाजपा विधायक बी.ए. बसवराज द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने हत्या के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा, ''आप एक जन प्रतिनिधि हैं। आपको साहस के साथ आगे बढ़कर यह कहना चाहिए कि मैं किसी भी तरह की पूछताछ का सामना करने के लिए तैयार हूं।'' प्रधान न्यायाधीश के साथ पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची भी शामिल थे। बसवराज को 15 जुलाई, 2025 को शिवप्रकाश उर्फ बिकला शिव की हत्या के मामले में बतौर आरोपी नामजद किया गया है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका पर सुनवाई करने को लेकर अनिच्छा जताए जाने के बाद बसवराज की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अर्जी वापस लेने की अनुमति मांगी। पीठ ने याचिकाकर्ता को नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। पीठ ने कहा, ''हम संबंधित न्यायालय से नियमित जमानत के आवेदन पर शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध करते हैं।''

रोहतगी ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि याचिकाकर्ता का हत्या से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि मामला संपत्ति का विवाद था और ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि बसवराज का इससे कोई संबंध था। प्रधान न्यायाधीश ने टिप्पणी की, भूमि हड़पने वालों को आमतौर पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है।''

पीठ ने कहा कि हत्या के मामले में अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते समय अदालत को ''बहुत सतर्क'' रहना चाहिए। कुछ आरोपों का जिक्र करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि ये जांच के विषय हैं। उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को पारित आदेश में कहा था, यह देखते हुए कि अग्रिम जमानत देना एक असाधारण राहत है जिसे बढ़ाया जा सकता है। अदालत की राय है कि याचिकाकर्ता की राजनीतिक रसूख और मृतक की मां का उसके निर्वाचन क्षेत्र में रहने के तथ्य के मद्देनजर, निष्पक्ष जांच में बाधा आने की आशंका है और यह भी अग्रिम जमानत से इनकार करने का एक कारण हो सकता है।

नशे में धुत्त बैंककर्मी ने थाने में किया हंगामा, गिरफ्तार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मंगलुरु।कर्नाटक के मंगलुरु में एक थाने में मामूली शिकायत दर्ज कराने पहुंचे नशे में धुत्त एक बैंक कर्मचारी को पुलिस अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान मंजप्पा सुरेंद्रन के रूप में हुई है और वह बैंक की येयाडी शाखा का कर्मचारी है। पुलिस के मुताबिक, उसने कई बार पुलिस को फोन लगाया और रिहाइशी परिसर में युवाओं द्वारा बैडमिंटन खेले जाने से परेशानी के बारे में शिकायत की। अधिकारी ने बताया कि पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं करने पर सुरेंद्रन बुधवार देर शाम कथित तौर पर नशे की हालत में कवूर थाना पहुंचा और तुरंत शिकायत दर्ज करने का दबाव बनाया। उन्होंने बताया कि जब पुलिसकर्मियों ने उसकी बात नहीं मानी तो बैंककर्मी ने इस मामले को वरिष्ठ अधिकारियों तक ले जाने की धमकी दी।

पुलिस ने बताया कि अधिकारियों ने उसे नशे की हालत में देखकर समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं माना और फिर उसने अपनी पत्नी के साथ स्कूटर पर थाने से भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने उसे पद्मानाडी के पास पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक, चिकित्सा जांच में उसके नशे की हालत में होने की पुष्टि हुई और उसे अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

सार्वजनिक सूचना

गडग II-ए ट्रांसमिशन लिमिटेड (जीआईआई-एटीएल)

सार्वजनिक सूचना गडग पी.एस. से कोप्पल पी.एस. के बीच 400 केवी डी/सी ट्विन HTLS गडग-कोप्पल पारेषण लाइन के चार्ज किए जाने हेतु

इसके द्वारा जनता को सूचित किया जाता है कि मेसर्स गडग II-ए ट्रांसमिशन लिमिटेड ने गडग पुलिस स्टेशन से कोप्पल पुलिस स्टेशन तक 400 केवी डीसी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया है। उपरोक्त ट्रांसमिशन लाइन कर्नाटक राज्य के गडग और कोप्पल जिलों के निम्नलिखित गांवों, तालुकों और जिलों से होकर गुजरती है:

1. जीआईआई-एटीएल गडग पीएस (गांव: गुलागुली, तालुक: गजेंद्रगढ़, जिला: गडग) – कोप्पल पीएस (गांव: तालाकल, तालुक: कुकनु:, जिला: कोप्पल) –49.768 किलोमीटर

क्र.स.	गांव का नाम	तहसील	जिला
1	मुशिगेरी, चिगलागुंडी, सांतागेरी, नल्लूर, कलिंगनूर, रुद्रपुर, अमरागट्टी, लक्कलाकट्टी, गुलागुली, अलागुंडी, द्यामुंशी, बेविनकट्टी, सुडी, निदागुंडी, निदागुंडी कोप, हल्केरी, डिंडूर, राजुर, इटगी, कालकापुर, कोडगानूर	गजेंद्रगढ़	गडग
2	कतरला, सिरागुम्पी, संकनूर, होसुर, म्यागेरी, मुधोल, करमुडी, संगनाल, बंदेहल, टोंदेहल, येलबर्गा, कल्लूर	येलबुर्गा	कोप्पल
3	अदूर, राजूर, हिरे शंकरबंदी, द्यमपुर, कुक्नूर, गोरलुकोप्पा, च्लन्नप्पनहल्ली ध्यनपनहल्ली, मसाबाहनचिनाला, चिक्केनाकोप्पा, बटप्पनहल्ली, मंडलगेरी, निताली, मालेकोप्पा, मन्नापुरा, इटागी, लिंगपुरा, ताड़कल, तलबल, बन्नीकोप्पा, अदावल्ली, कोमलपुरा, चित्तपुरा	कुकनुरु	कोप्पल

ट्रांसमिशन लाइन को 16 फरवरी 2026 अथवा उसके पश्चात किसी भी दिन विद्युतीकृत/चालू माना जाएगा। इसलिए, सभी को सूचित किया जाता है कि वे टावरों पर न चढ़ें और न ही टावरों, टावर के हिस्सों और कंडक्टरों आदि के संपर्क में आएं। ट्रांसमिशन लाइन के टावरों और कंडक्टरों के संपर्क में आने से जानलेवा दुर्घटना हो सकती है। जनता को सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त किसी भी कार्य में शामिल न हों और दूसरों को भी ऐसे कार्य करने से रोकें, ताकि किसी भी दुर्घटना को रोका जा सके।

16 फरवरी 2026 को या उसके बाद किसी भी दिन से ट्रांसमिशन लाइन को विद्युतीकृत/चालू माना जाएगा। सभी को सूचित किया जाता है कि मेसर्स गडग II-ए ट्रांसमिशन लिमिटेड (GII-ATL) किसी भी व्यक्ति द्वारा सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन के कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना/क्षति/जीवन, पशुधन और सामग्री/संपत्ति की हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

वरिष्ठ प्रबंधक (ट्रांसमिशन)

पता: सी/ओ रेवना सिद्धेश्वर निलय, न्यू पुलिस स्टेशन के पास, रॉन रोड, गजेंद्रगड़ा, जिला- गडग कर्नाटक- 582114
ईमेल: shaik,akbar@renew,com, संपर्क: 9704303431

द्रमुक कांग्रेस गठबंधन पर निर्भर नहीं, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री स्टालिन करेंगे : राजाकन्नप्पन

मदुरै। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के वरिष्ठ नेता आर. एस. राजाकन्नप्पन ने कांग्रेस के साथ पार्टी के गठबंधन को लेकर दृढ़, आत्मनिर्भर रुख का संकेत देते हुए कहा कि द्रमुक अपनी राजनीतिक गतिविधियां गठबंधन पर निर्भर होकर नहीं चला सकता। वन एवं खादी मंत्री राजाकन्नप्पन ने बुधवार को यहां एक कार्यक्रम में कहा कि गठबंधन संबंधी मामलों पर मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन निर्णय लेंगे, लेकिन पार्टी का रुख स्पष्ट है-वे आएं तो आएं, जाएं तो जाएं।

राजाकन्नप्पन ने द्रविड़ आंदोलन के इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी की सफलता अन्य राजनीतिक दलों पर निर्भरता के बजाय जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों पर आधारित है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में अपनी जड़ें नहीं जमा सकती। उन्होंने यह भी दावा किया कि अन्नाद्रमुक अब समाप्त हो चुकी ताकत है। उन्होंने कहा, वे 'कुन्नाकुडी में अन्नकावड़ी' (पारंपरिक चढ़ावा) भी चढ़ा लें, तब भी भाजपा यहां पैर नहीं जमा सकती। अन्नाद्रमुक कभी थी, लेकिन एमजीआर और जयललिता के साथ ही उसका अंत हो गया। द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत का जिक्र करते हुए राजाकन्नप्पन ने कहा कि सी. एन. अन्नादुरै ने रॉबिन्सन पार्क में बारिश के बीच इस आंदोलन की स्थापना की थी।

ज्ञान को कर्म में बदलें, यही दीक्षांत का सच्चा संदेश : राज्यपाल बागड़े

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं, बल्कि जीवन के नए चरण की शुरुआत है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अर्जित ज्ञान को कर्म में बदलते हुए राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनें। राज्यपाल ने कहा कि जिस समाज में बेटियां आगे बढ़ती हैं, वही समाज तेजी से विकास करता हैयह गर्व का विषय है कि आज स्वर्ण पदकों में बड़ी संख्या में बेटियां अग्रणी रही हैं।

राज्यपाल बागड़े गुरुवार को जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के 22वें दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने भारतीय ज्ञान परंपरा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत की शिक्षा परंपरा सदियों से समग्र विकास, नैतिक मूल्यों और आत्मबोध पर आधारित रही है। उन्होंने कहा कि हमारे वेद, उपनिषद और गुरुकुल प्रणाली ने केवल विद्या नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण की शिक्षा दी है। विश्वविद्यालयों का दायित्व है कि वे आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय करें।

इससे विद्यार्थी केवल कुशल पेशेवर ही नहीं, बल्कि संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। उन्होंने आह्वान किया कि युवा अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक मंच पर भारत का नेतृत्व करें।

उन्होंने कहा कि आज का युग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता का है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 'बोधन एआई स्टैक' जैसी पहल शिक्षा के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करेगी, जिससे विद्यार्थियों को अपनी भाषा में इंटरएक्टिव शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध होगी। साथ ही उन्होंने आगाह किया कि एआई मानव मस्तिष्क का स्थान नहीं ले सकती, इसे संदर्भ के रूप में उपयोग करें, पर बौद्धिक क्षमता का विकास स्वयं करें। उन्होंने राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ जीवन का ध्येय निर्धारित करने और विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने का आह्वान किया। समारोह में कुल 52,682 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध उपाधियां प्रदान की गईं तथा 59 स्वर्ण पदक वितरित किए गए।

स्वास्थ्य का अधिकार कानून पर मंत्री के बयान को लेकर राजस्थान विधानसभा में विपक्ष ने किया हंगामा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य का अधिकार कानून के तहत नियम बनाने के मुद्दे पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के जवाब को लेकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि यह अधिनियम 12 अप्रैल 2023 को अधिसूचित हुआ था, लेकिन दो साल बाद भी इसके नियम नहीं बने। उन्होंने पूछा कि नियम क्यों नहीं बनाए गए। जवाब में मंत्री खींवसर ने कहा कि यह कानून कांग्रेस सरकार चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ के लिए लाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि विधेयक अचानक पेश किया गया था, और हितधारकों की राय शामिल नहीं की गई।

खींवसर ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार पहले से ही मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (एमएए) योजना लागू कर रही है, जो व्यापक है और इसके चलते स्वास्थ्य का अधिकार कानून की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में नियम क्यों नहीं बनाए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वह नियम बनाएगी या नहीं।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदस्यों को अपनी सीटों पर लौटने को कहा और चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर सदन स्थगित कर दिया जाएगा। थोड़ी देर के व्यवधान के बाद विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर लौट आए।

बाद में कांग्रेस विधायकों ने मंत्री के बयान का विरोध करते हुए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मंत्री के बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि विधानसभा में चिकित्सा मंत्री का यह कहना कि स्वास्थ्य का अधिकार कानून की जरूरत नहीं है, निंदनीय है और गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने चिरंजीवी योजना और निरोगी राजस्थान योजना जैसी सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजनाओं के बावजूद स्वास्थ्य का अधिकार कानून की परिकल्पना की थी ताकि आपात स्थिति में कोई भी मरीज इलाज से वंचित न रहे। गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार अधिनियम के तहत नियम बनाने में विफल रही है और अब बहाने बना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का उद्देश्य जनता को महंगे इलाज से बचाना था, जबकि भाजपा सरकार चिकित्सा जगत से जुड़े शक्तिशाली समूहों के दबाव में कानून को ही अनावश्यक बता रही है।

किसानों के लिए आमदनी की असीम संभावनाओं के द्वार खोलेगा आंवला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। जयपुर जिले में कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जिला प्रशासन द्वारा 13 फरवरी को दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में जिला स्तरीय आंवला क्रेताविक्रेता सम्मेलन एवं प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार पंच गौरव योजना के अंतर्गत एक जिलाएक उपज आंवला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित यह कार्यक्रम जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में संपन्न होगा।

यह सम्मेलन किसानों, व्यापारियों, प्रसंस्करण इकाइयों और उद्यमियों को एक साझा मंच प्रदान करेगा, जहां आंवला उत्पादन से जुड़े विभिन्न आयामों पर संवाद स्थापित होगा तथा उत्पादकों को विपणन के नए अवसर प्राप्त होंगे। सम्मेलन में जयपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से लगभग 700 से अधिक किसान, क्रेता, एफपीओ प्रतिनिधि, व्यापारी एवं कृषि उद्यमी भाग लेंगे।

मुख्य आयोजना अधिकारी डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि कार्यक्रम में स्थानीय कृषि उत्पादों की विशिष्ट पहचान को बढ़ावा देने के लिए जयपुर जिले की पंच गौरव उपजों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इन स्टॉलों के माध्यम से पारंपरिक कृषि उत्पादों के साथ-साथ उनके मूल्यवर्धित स्वरूप को प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और बाजार विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा।

उद्यानिकी विभाग के उपनिदेशक हरलाल सिंह बिजारनियां ने बताया कि प्रदर्शनी में आंवला से तैयार किए गए विभिन्न उत्पादों जैसे मुरब्बा, कैंडी, जूस, चूर्ण और औषधीय उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही आधुनिक कृषि उपकरणों, प्रसंस्करण तकनीकों, पैकेजिंग, भंडारण एवं गुणवत्ता संवर्धन से जुड़े नवाचारों को भी प्रदर्शित किया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान कृषि एवं उद्यानिकी विशेषज्ञ किसानों को उन्नत उत्पादन तकनीकों, गुणवत्ता मानकों, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और बाजार रणनीतियों की जानकारी देंगे। यह सम्मेलन न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा, बल्कि कृषि आधारित उद्योगों के विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

ट्रेलर ने बाइक टक्कर मारी, तीन बच्चों की मौत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोटा। राजस्थान के बूंदी जिले में एक ट्रेलर ट्रक के बाइक को टक्कर मारने से छह से 12 साल आयुवर्ग के तीन बच्चों की मौत हो गई जबकि उनके पिता गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, यह घटना जिले के डाबी थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर बुधवार देर शाम हुई। इस घटना के बाद परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और शवों को सड़क पर रख दिया तथा आरोपी ट्रक चालक की गिरफ्तारी की मांग की, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग एक घंटे तक यातायात बाधित रहा।

पुलिस के अनुसार, मदन बंजारा बुधवार रात को मोटरसाइकिल से अपने गांव प्राणाना जा रहे थे। उनके साथ उनके तीन बच्चे - सुमन (6), अंकित बंजारा (8), करण बंजारा (12) भी थे। तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने कथित तौर पर उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि टक्कर भीषण थी और चारों पीड़ित सड़क पर घिसटते चले गए।

तीनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें कोटा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है।

क्षेत्र निरीक्षक हेमराज शर्मा ने बताया कि ट्रक कथित तौर पर तेज गति से चलाया रहा था, जिसके कारण चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और उसने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के बाद चालक घटनास्थल से फरार हो गया और उसकी तलाश जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि वाहन को जब्त कर लिया गया है। घटना के बाद, परिवार के सदस्य और ग्रामीण दुर्घटनास्थल पर जमा हो गए और राजमार्ग के 'स्लिप-लेन' पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के कारण एनएच-27 पर लगभग एक घंटे तक यातायात बाधित रहा और दोनों लेन पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि तेज गति से चलने वाले वाहनों के कारण इस मार्ग पर अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं और उन्होंने चालक की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ितों के परिवार को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों को नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई और सहायता का आश्वासन दिया गया। शर्मा ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और बृहस्पतिवार सुबह परिजनों को सौंप दिया गया।

विधानसभा क्षेत्र धोद में 282 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित : दिया कुमारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

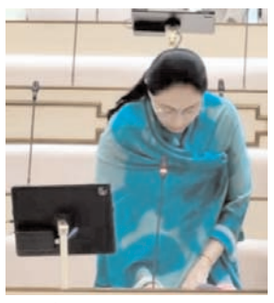

जयपुर। उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि विधान सभा क्षेत्र धोद में कुल 282 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं,जिनमें से 62 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवनों में, 22 किराये के भवनों में, 142 विद्यालयों में, 48 अन्य राजकीय भवनों में एवं 8 निजी निःशुल्क भवनों में संचालित हैं। उन्होंने बताया कि 2 आंगनबाड़ी केन्द्रों सांवलोदा पुरोहितान एवं सांवलोदा लाडखानी के भवन निर्माणाधीन हैं। उप मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य गोरधन द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रही थीं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिए निर्धारित मापदण्ड तय किये गए हैं। इसके तहत 400 से 800 की आबादी पर एक आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जाता है। इसी प्रकार 800 से 1600 की आबादी पर 2 केन्द्र, 1600 से 2400 की आबादी पर 3 केन्द्र तथा इसके पश्चात प्रत्येक 800 के गुणक पर एक आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि जनजातीय इलाकों, पहाड़ी, मरुस्थलीय एवं दुर्गम स्थानों पर 300 से 800 की आबादी पर एक आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जाता है। एक केन्द्र के लिए न्यूनतम 600 वर्ग फीट भूमि की अनिवार्यता है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के नवीन भवनों का निर्माण नरेगा योजना के अन्तर्गत कन्वर्जेन्स के माध्यम से करवाया जा रहा है। केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार एक भवन के निर्माण के लिए 12 लाख रुपये की राशि निर्धारित है। इसमें से 2 लाख रुपये विभाग द्वारा, 8 लाख नरेगा कन्वर्जेन्स के माध्यम से तथा शेष 2 लाख रुपये 15वें वित्त आयोग या जिला परिषद के अन्य किसी अनटाइड फण्ड से लिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र धोद में वर्तमान में 11 राजस्व ग्रामों में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित नहीं है। केन्द्र नहीं होने की स्थिति में गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सुविधाएं दी जाती हैं।

इससे पहले विधायक गोरधन के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उप मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने कहा कि सरकार विभागीय भवन के अलावा अन्य राजकीय अथवा किराये के भवनों में संचालित किये जाने वाले आंगनबाडी केन्द्रों के लिए पृथक भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है। नवीन भवन निर्माण स्थानीय निकाय अथवा ग्राम पंचायत से निःशुल्क भूमि आवंटन होने तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं कार्य की परस्पर प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाना निर्भर करता है।

वर्तमान में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। नवीन आंगनबाडी केन्द्र खोलने हेतु परीक्षण करवाया जाकर गुणावगुण एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर पारस्परिक प्राथमिकतानुसार निर्णय किया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दी गई सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। महिला अधिकारिता विभाग द्वारा सक्षम जयपुर अभियान के अंतर्गत साथिनों के लिए एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य जमीनी स्तर पर कार्यरत साथिनों को विभागीय योजनाओं, नियमों एवं अधिनियमों की अद्यतन एवं व्यावहारिक जानकारी प्रदान कर उन्हें और अधिक प्रभावी बनाना है। महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक डॉ. राजेश डोगीवाल ने बताया कि जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशों की अनुपालना में 12 फरवरी को पंचायत समिति मुख्यालय दूदू एवं बस्सी पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें पंचायत समिति दूदू, मौजमाबाद, फागी, माधोराजपुरा तथा बस्सी, तुंगा, आंधी एवं जमवारामगढ़ क्षेत्र की साथिनों ने सहभागिता की।

उन्होंने बताया कि सक्षम जयपुर अभियान के तहत आयोजित इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वर्क फ्रॉम होम योजना, मुख्यमंत्री उद्यम प्रोत्साहन योजना, कालीबाई भील उड़ान योजना सहित विभिन्न महिला हितैषी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। साथ ही संबंधित अधिनियमों एवं नियमों की समझ विकसित कराई जा रही है, ताकि साथिनें अपने-अपने क्षेत्र में पात्र महिलाओं को योजनाओं का लाभ दिलाने में सक्रिय भूमिका निभा सकें। वर्क फ्रॉम होम योजना से संबंधित उद्यमी संस्थाओं को भी आमंत्रित किया गया, जिन्होंने स्वरोजगार के अवसरों पर मार्गदर्शन प्रदान किया। डॉ. राजेश डोगीवाल ने बताया कि 13 फरवरी को चौमूं पंचायत समिति मुख्यालय एवं आमेर स्थित वन स्टॉप सेंटर पर पंचायत समिति जालसू, गोविंदगढ़, झोटवाड़ा, शाहपुरा, आमेर एवं जमवारामगढ़ क्षेत्र की साथिनों के लिए कार्यशाला आयोजित की जाएगी। वहीं दिनांक 16 फरवरी 2026 को जोबनेर, सांगानेर एवं चाकसू पंचायत समिति मुख्यालयों पर पंचायत समिति जोबनेर, सांभर, किशनगढ़ रेनवाल, चाकसू, कोटखावदा एवं सांगानेर क्षेत्र की साथिनों के लिए आमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शोधार्थी से ऐंठे 10 लाख रुपये

जयपुर। राजस्थान के जयपुर में अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए) के एक शोधार्थी से 10 लाख रुपये ऐंठने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी पिछले एक साल से शोधार्थी को ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस उपायुक्त (उत्तर) करन शर्मा ने बताया कि तकनीकी विश्लेषण और मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने सील्वेस्टर फर्नांडीस (47) को गिरफ्तार किया, जो मुम्बई हाल अजमेर रोड का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि 10 फरवरी को कर्नाटक के बेलगांव निवासी रवि कुमार हणमंत (28) ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि फर्नांडीस नाम के व्यक्ति ने शुरू में जान-पहचान बढ़ाई और बाद में उसे कथित अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी पुलिस में मामला दर्ज कराने का डर दिखाकर पिछले एक साल में उससे लगभग 10 लाख रुपए ऐंठ चुका था।

जो कुर्सी-बचाने फिरते रहे, उन्हें सवाल का अधिकार नहीं : पटेल

जिसकी जैसी संस्कृति होती है, उसको वैसा ही याद रहता है। हमने घोषणाएं बचाकर रखी हैं, ऐसा अनुमान लगाने वाले अंतर्यामी को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि घोषणाएं लगातार होंगी, विकास निरंतर चलेगा।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा- जो होटलों में बंद रहे, तत्कालीन मुख्यमंत्री अपने ही उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते थे, उसको मैं यहां दोहराना भी नहीं चाहता हूं। पटेल ने कहा- अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली और अन्य जगह फिरते रहे। उन्हें ऐसा प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को सातों संभागों के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंत्री जोगाराम पटेल ने यह कहा। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद थे।

जोगाराम पटेल ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बयान पर पलटवार करते हुए कहा- जिसकी जैसी संस्कृति होती है, उसको वैसा ही याद रहता है। उन्होंने कहा- हमने घोषणाएं बचाकर रखी हैं, ऐसा अनुमान लगाने वाले अंतर्यामी को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि घोषणाएं लगातार होंगी, विकास निरंतर चलेगा। सरकार में कोई खींचतान नहीं है। हम एक मन, एक राय और एक परिवार के रूप में राजस्थान के विकास के लिए काम करते रहेंगे। दरअसल, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा था- मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री) के बीच प्रतिस्पर्धा है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं वित्त मंत्री को करने नहीं दी।

यह बजट राजनीतिक परंपराओं से हटकर है। आज तक बजट में रेवड़ियां बंटती रही हैं। यह बजट रेवड़ी संस्कृति पर वैचारिक प्रहार है। उन्होंने कहा- इस बजट में हमारा विजन है कि किस तरह से राजस्थान समृद्ध और विकसित बने। इस बजट में हमारी नीति और परिकल्पनाएं हैं। बजट में अल्पकालीन लोकप्रियता की बजाय दीर्घकालीन स्थिरता को प्राथमिकता दी गई हैं।

'खेजड़ी बचाओ' आंदोलन जारी, मुख्यमंत्री भजनलाल से मुलाकात के बाद भी बीकानेर में क्रमिक अनशन

बीकानेर/दक्षिण भारत । बीकानेर में 'खेजड़ी बचाओ' आंदोलन के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात के बाद भी आंदोलन जारी है। बिश्नोई समाज के करीब एक सौ पचास लोग विष्णु धर्मशाला के सामने क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक पूरे राजस्थान के लिए खेजड़ी बचाओ कानून नहीं बनाया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बिश्नोई समाज के संत सच्चिदानंद ने कहा कि कुल्हाड़ी उनकी भारी है, सर हमारे ज्यादा हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि समाज खेजड़ी वृक्षों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और कानूनी प्रावधान बनने तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा।

आगामी 17 फरवरी को बीकानेर से कुछ किलोमीटर दूर जुम्बेश्वर महाराज का मेला आयोजित होना है, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना रहती है। इस बार आयोजन समिति ने तय किया है कि श्रद्धालु जुम्बेश्वर महाराज के ढोक लगाने के बाद व्रत करने के लिए बीकानेर स्थित विष्णु धर्मशाला पहुंचेंगे, जहां आंदोलन चल रहा है।

सूत्रों के अनुसार राजस्थान सरकार खेजड़ी बचाओ आंदोलन को समाप्त करने के लिए पूरे प्रदेश में सख्त कानून बनाने पर सहमत हो गई है। बताया जा रहा है कि सरकार के प्रतिनिधि लिखित आश्वासन लेकर शाम से पहले बिश्नोई धर्मशाला पहुंच सकते हैं।

मेला

हरियाणा के फरीदाबाद में '39वें सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेले' के दौरान राजस्थान के कलाकार।

आत्मनिर्भर भारतः असम राइफल्स अपने श्वान दस्ते में अब भारतीय नस्ल के कुत्तों को शामिल करेगा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जोरहाट (असम)/भाषा। केंद्र सरकार के स्वदेशीकरण के आह्वान को मजबूती प्रदान करते हुए असम राइफल्स अपने विभिन्न अभियानों को अंजाम देने के लिए अपने दस्ते में भारतीय नस्ल के कुत्तों को शामिल करने की योजना बना रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

'असम राइफल्स श्वान प्रशिक्षण केंद्र' के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल आलोक पालेई ने 'पीटीआई-भाषा' को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत सबसे पुराने अर्धसैनिक बल ने पहले ही एक प्रायोगिक परियोजना के तहत 'तंगखुल हुई' नस्ल के कुत्तो को अपने 'श्वान दस्ते' में शामिल कर लिया है। उन्होंने बताया कि बल अप्रैल से कोम्बाई नस्ल को भी शामिल करने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा, ''केंद्रीय गृह मंत्री (अमित शाह) ने हमेशा हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की वकालत की है। वे सभी बलों के श्वान दस्तों में भारतीय नस्ल के कुत्तों की संख्या बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। तब से हम अपने उद्देश्यों के लिए एक स्वदेशी नस्ल की पहचान करने पर काम कर रहे हैं।

हमारे मंत्री पहलवान, इनकी कमाल साहब से कुश्ती करा देंगे : खन्ना

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार के मंत्री पहलवान हैं और इनकी कमाल साहब से कुश्ती करा दी जायेगी।

विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन बृहस्पतिवार को विधानसभा में शून्यकाल में समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्य इंजीनियर सचिन यादव एवं अन्य सदस्यों द्वारा कार्यस्थगन के तहत खेल के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग किए जाने पर खन्ना ने कहा, ''हमारे मंत्री रेसलर (पहलवान) हैं और इनकी कमाल साहब से कुश्ती करा देंगे। '' विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने हस्तक्षेप करते हुए हंसी के माहौल में कहा कि यह कुश्ती विधानसभा में नहीं होनी चाहिए।

सचिन यादव ने ग्राह्यता पर बल देते हुए कहा कि खेल के मद में बजट कम प्रस्तावित किया गया है और कई महत्वपूर्ण मदों में बजट शून्य है। वह सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग पर जोर दे रहे थे। इस बीच सपा के वरिष्ठ सदस्य कमाल अख्तर ने कहा कि इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश का खेल में प्रदर्शन बहुत पीछे है और अगर वित्त मंत्री जी बजट बढ़ा दें तो प्रतिभाओं का विकास होगा। अख्तर ने कहा कि बेहतर होता कि जिस विभाग के मंत्री हों उन्हें भी उसके बारे में अनुभव हो लेकिन हमारे खेल मंत्री तो खेल समझते ही नहीं हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने अख्तर के इस बयान पर टोकते हुए कहा , ''हमारे मंत्री पहलवान हैं और हम इनकी कमाल साहब से कुश्ती करा देंगे।''

हालांकि इस बीच खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश यादव ने विपक्षी सदस्यों की बात काटते हुए हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट से लेकर कई खेलों में अपनी विशेषता गिनाई।

यादव ने बजट में विपक्षी सदस्यों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य में 15 हजार से ज्यादा ग्राम सभाओं में खेल का मैदान विकसित किया गया है और अन्य पर कार्य चल रहा है। उन्होंने खेल के क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाएं भी गिनाईं। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार युवाओं, छात्रों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है।

यादव ने सपा सरकार के समय में खेल के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का तुलनात्मक ब्यौरा भी दिया। उन्होंने कहा कि वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम योगी आदित्यनाथ सरकार ने बनाया है तथा मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मेरठ में पहला खेल विश्वविद्यालय बन रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने सपा सदस्यों के कार्य स्थगन के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया।

ओडिशा में डॉल्फिन की संख्या 765 पहुंची

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेहरामपुर (ओडिशा)/भाषा। ओडिशा की चिल्का झील में इरावदी डॉल्फ़िन की संख्या वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की वन्यजीव शाखा द्वारा की गई नवीनतम गणना में 159 पर ही स्थिर मिली। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खारे पानी की झील में इस प्रजाति की संख्या 2025 में भी 159 थी।

इरावदी डॉल्फ़िन के अलावा, चिल्का में हिंद-प्रशांत और हिंद महासागर प्रजातियों की 16 हंपबैक डॉल्फ़िन भी दर्ज की गईं। अधिकारियों ने बताया कि 2025 में झील में 15 हंपबैक डॉल्फ़िन देखी गई थीं। संख्या आकलन कवायद के दौरान ओडिशा तट और चिल्का झील में कुल छह प्रजातियों की 765 डॉल्फ़िन देखी गईं। इनमें 208 इरावदी डॉल्फ़िन, 495 हंपबैक डॉल्फ़िन, 55 बॉटलनेक डॉल्फ़िन, तीन स्पिनर डॉल्फ़िन और दो फिनलेस पोरपोइज़ शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक, भितरकनिका समुद्री अभयारण्य में नौ इरावदी डॉल्फ़िन, पुरी वन्यजीव प्रभाग क्षेत्र में 12, बेरहामपुर प्रभाग में 13 और बालासोर वन्यजीव प्रभाग में 15 इरावदी डॉल्फ़िन देखी गई हैं। राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) (वन्यजीव) प्रेम कुमार झा ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ओडिशा में पिछले पांच वर्षों में डॉल्फ़िन की सबसे अधिक संख्या 765 दर्ज की गई है। उन्होंने कहा, मजबूत संरक्षण प्रयासों, पर्यावास संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी ने समुद्री जैव विविधता संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत प्रयासरत : रेड्डी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बृहस्पतिवार को कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा तेज होने के बीच भारत अपनी आयात निर्भरता घटाकर 'विकसित भारत' दृष्टि के अनुरूप खनिज आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सक्रिय है।

रेड्डी ने यहां अन्वेषण लाइसेंस (ईएल) की दूसरी किस्त की नीलामी के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा, भारत आयात पर निर्भरता कम करने और 'विकसित भारत' के अनुरूप खनिज आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है।

उन्होंने खनन क्षेत्र में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि मजबूत खनिज अन्वेषण पारिस्थितिकी का विकास किया जा रहा है।

मंत्री ने राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास न्यास (एनएमईटी) के विस्तारित दायरे और अन्वेषण को मजबूत करने के लिए 'समन्वित सरकारी दृष्टिकोण' पर जोर दिया। उन्होंने डेटा एकीकरण, आंकड़ा-आधारित निर्णय और खनिज संभावनाओं की व्यवस्थित पहचान को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने उद्योग जगत से अनुसंधान, नवाचार और समन्वय बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा कि सरकार निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और खनिज अन्वेषण ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।

रेड्डी ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से भी खनिज अन्वेषण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।सरकार ने दूसरे चरण में 11 अन्वेषण लाइसेंस ब्लॉक की नीलामी शुरू की है। इनमें दुर्लभ मृदा तत्व, सोना, हीरा और तांबा सहित अन्य खनिज शामिल हैं। ये ब्लॉक आठ राज्यों में स्थित हैं।

यह झूठ है कि मैं बिरला के कक्ष में कांग्रेस सांसदों को उकसा रही थी : प्रियंका गांधी

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा ने बृहस्पतिवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू के उस आरोप को झूठ करार दिया कि वह अपने पार्टी सांसदों को उस समय उकसा रही थीं जब उन्होंने कथित तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कक्ष में उग्र व्यवहार किया था। उन्होंने कहा, ''हमने किसी को गाली नहीं दी।''

उनकी इस टिप्पणी से एक दिन पहले रीजीजू ने दावा किया था कि 20 . 25 कांग्रेस सांसदों ने बिरला के कक्ष में उन्हें अपशब्द कहे और वहां मौजूद वरिष्ठ नेताओं के.सी. वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी ने उन्हें नहीं रोका। रीजीजू ने कहा था, ''वे (कांग्रेस सांसद) उन्हें उकसा रहे थे। अगर हमारे सांसद किसी के साथ दुर्व्यवहार करते, तो हमारे नेता उन्हें रोकते। लेकिन उनके (कांग्रेस) नेता सांसदों को झगड़ने के लिए उकसा रहे थे।'' रीजीजू के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ''हमने किसी को गाली नहीं दी। एक-दो सांसद आक्रोशित थे और उन्होंने अपनी बात रखी।'' उन्होंने यह भी कहा, ''यह झूठ है कि मैं उन्हें उकसा रही थी। मैं चुपचाप बैठी थी। अंत में मैंने शांतिपूर्वक अध्यक्ष से कुछ बातें कहीं।''

प. बंगाल के राज्यपाल ने निष्पक्ष ढंग से चुनाव संपन्न होने की उम्मीद जताई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बृहस्पतिवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद एसआईआर अब एक ''बंद अध्याय'' बन चुका है और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निर्वाचन आयोग राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव निष्पक्ष रूप से करायेगा।

बोस ने कहा, ''उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का अध्याय समाप्त हो चुका है। यदि इस प्रक्रिया के संचालन में कोई खामी पाई जाती है, तो निश्चित रूप से उसे संतुलित तरीके से दूर किया जायेगा।'' उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राज्यों को स्पष्ट कर दिया था कि वह मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कवायद में किसी को भी बाधा डालने की अनुमति नहीं देगा।

विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने उम्मीद व्यक्त की कि निर्वाचन आयोग अपनी जिम्मेदारी निष्पक्ष और सकारात्मक रूप से निभायेगा। उन्होंने कहा, ''निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि बंगाल में चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न हों।''

राज्यपाल ने चुनावी प्रक्रिया और इसे संचालित करने के लिए जिम्मेदार संस्थानों में जनता के भरोसे को बनाये रखने के महत्व पर जोर दिया।

अरुणाचल सरकार अधिक संख्या में कयाकिंग प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी : मुख्यमंत्री खांडू

ईटानगर/भाषा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार पूरे राज्य में कयाकिंग और कैनोइंग प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ाएगी।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, उन्होंने तवांग में सुरम्य तवांगचू नदी पर 'तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप' के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करने के बाद कहा कि सरकार इस टूर्नामेंट को एक प्रमुख वार्षिक खेल आयोजन बनाएगी ताकि युवाओं की भागीदारी, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके।

खांडू ने इस अवसर पर राज्य की विशाल नदियों के प्राकृतिक लाभ पर प्रकाश डाला और कहा कि पांच नदी बेसिनों को प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव आगे की कार्रवाई के लिए राज्य के युवा मामलों और खेल सचिव को भेज दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार तकनीकी टीमों और भारतीय कयाकिंग एवं कैनोइंग एसोसिएशन के समन्वय से राज्य में इस खेल को व्यवस्थित रूप से बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा 'तवांगचू टाइड्स अंतरराष्ट्रीय कयाकिंग चैंपियनशिप' के लिए आधिकारिक तौर पर वित्तीय सहायता की शुरुआत करने की घोषणा की और इसे युवा मामलों एवं खेल विभाग का वार्षिक आयोजन घोषित किया। उन्होंने बताया कि इस आयोजन को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए कॉरपोरेट प्रायोजकों को शामिल करने और सीएसआर साझेदारी तलाशने के प्रयास किए जाएंगे।

असम के डिब्रूगढ़ में बाईपास पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 14 फरवरी को असम के डिब्रूगढ़ जिले में मोरान बाईपास पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

मंत्रालय के अनुसार, इस सुविधा के शुरू होने से राजमार्ग के एक निर्धारित हिस्से को वैकल्पिक रनवे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा, जहां आपात स्थिति में लड़ाकू विमान, परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर को उतारा व रवाना किया जा सकेगा।

मंत्रालय ने कहा कि यह सुविधा दूर-दराज के क्षेत्रों में मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएआरडी) अभियानों के दौरान भी महत्वपूर्ण साबित होगी। रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा, असम राज्य एक ऐतिहासिक उपलब्धि का साक्षी बनने जा रहा है। डिब्रूगढ़ जिले के मोरान बाईपास पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (ईएलएफ) का 14 फरवरी को उद्घाटन होगा। यह ईएलएफ पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह की पहली सुविधा है।

राष्ट्रगान से पहले 'वंदे मातरम्' गाने के केंद्र के निर्देश पर बंगाल में सियासी घमासान शुरू

कोलकाता/भाषा। आधिकारिक समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के सभी छह छंद को राष्ट्रगान जन गण मन से पहले गाए जाने के केंद्र के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तीखी राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने इस आदेश को रवींद्रनाथ टैगोर को कमतर दिखाने और चुनावी लाभ के लिए प्रतीकवाद बढ़ाने का प्रयास बताया, वहीं कांग्रेस ने इसे विभाजनकारी हथकंडा करार दिया।

भाजपा का कहना है कि यह केवल ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के गीत को पूरा सम्मान वापस दिलाने का प्रयास है। यह आदेश 28 जनवरी को जारी हुआ। बुधवार को अधिसूचित आदेश में गृह मंत्रालय ने कहा कि जब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान साथ-साथ गाए जाएं, तो वंदे मातरम् को जन गण मन से पहले गाना अनिवार्य है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा कि पार्टी को बंकिमचंद्र के योगदान को उजागर करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आरोप लगाया कि यह कदम टैगोर को कमतर दिखाने का प्रयास है।

सरकार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देती, अब मजदूरों को भी नहीं बोलने देगी : सुले

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की सांसद सुप्रिया सुले ने बृहस्पतिवार को श्रमिक संघों की हड़ताल का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देती और अब एक प्रस्तावित कानून के जरिये मजदूरों को भी नहीं बोलने देगी।

उन्होंने लोकसभा में 'औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026' पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि आज केंद्रीय श्रमिक संघ, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम संघ, बैंकिंग कर्मचारी, बीमा कर्मचारी, बिजली कर्मचारी, परिवहन श्रमिक और असंगित क्षेत्र के मजदूर हड़ताल पर हैं। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के एक संयुक्त मंच से जुड़े कर्मचारियों एवं श्रमिकों ने, केंद्र सरकार की ''मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी कॉरपोरेट समर्थक नीतियों को लेकर अपना विरोध'' जताने के लिए बृहस्पतिवार को एक दिवसीय हड़ताल की।

सुले ने कहा, ''राष्ट्र निर्माण करने वाले लोग हड़ताल पर हैं, जब हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। मैं निजीकरण के खिलाफ नहीं हूं...लेकिन कंपनियों को श्रमिकों ने बनाया है। उन्होंने मेहनत की। जिन्होंने इस देश को यहां तक लाया, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसानों और मजदूरों का रहा है। आज यह विधेयक उन्हीं के खिलाफ लाया गया है।''

उन्होंने 2023-24 की एक सरकारी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इसमें यह उल्लेख किया गया है कि देश में 2,12,990 फैक्टरी हैं, जिनमें 1,32,722 में 50 से कम मजदूर काम करते हैं। उन्होंने कहा मजदूर संघों के पंजीकरण के लिए पहले 20 श्रमिकों की जरूरत होती थी, आज यह संख्या बढ़ा कर 50 कर दी। उन्होंने कहा, ''इससे तो किसी भी मॉल में, बिग बास्केट जैसी दुकान आदि में यदि 50 से कम 49 श्रमिक भी हों तो वे श्रम संघ नहीं बना सकेंगे।''

परमाणु ऊर्जा के लिए 'पहले सुरक्षा, तब उत्पादन' का सिद्धांत : जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा को बताया कि देश का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र 'पहले सुरक्षा, तब उत्पादन' के सिद्धांत का पालन करता है। उन्होंने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से जुड़ी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने का प्रयास करते हुए यह बात कही। सिंह राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, ''...ऐसी आशंकाएं कभी-कभी बाहरी कारणों, राजनीतिक कारणों से भी उत्पन्न होती हैं। ऐसी कोई दुर्घटना कभी नहीं हुई है। हमारा सिद्धांत 'पहले सुरक्षा, तब उत्पादन' का है।'' सिंह ने कहा कि यह मुद्दा उठाया गया था कि कुडनकुलम में अन्य सभी रिएक्टरों से अपशिष्ट ईंधन का भंडारण किया जाएगा। यह बात वैज्ञानिक तर्क पर आधारित नहीं है। बिजली वितरण के संबंध में एक फार्मूला है, जिसके तहत 50% बिजली संयंत्र वाले राज्य के पास रहती है, 35 प्रतिशत पड़ोसी राज्यों को दी जाती है और 15 प्रतिशत राष्ट्रीय ग्रिड को भेजी जाती है।

ओडिशा सरकार ने 67,000 करोड़ रुपए के नवीकरणीय ऊर्जा समझौतों पर हस्ताक्षर किए

भुवनेश्वर/भाषा। ओडिशा सरकार ने 67,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं लगाने के लिए समझौतों पर बृहस्पतिवार को हस्ताक्षर किए। बयान के अनुसार, राज्य के ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ग्रिडको ने नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और एबीसी क्लीनटेक प्राइवेट लिमिटेड एंड एक्सिस एनर्जी वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ 6.8 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते किए। 'ओडिशा नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन 2026' के उद्घाटन के मौके पर उपमुख्यमंत्री के वी. सिंह देव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। बयान के अनुसार, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन 1,000 मेगावाट की पंप स्टोरेज परियोजना स्थापित करेगा जबकि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ग्राउंड-माउंटेड सौर, फ्लोटिंग सोलर पीवी एवं पंप स्टोरेज परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव रखेगी।

वाणसागर समझौताः बिहार को 5.75 एमएएफ और झारखंड को दो एमएएफ पानी मिलेगा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में कहा कि सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर बिहार और झारखंड सैद्धांतिक रूप से समझौता हो गया है।

जल संसाधन विभाग के बजट पर सरकार का पक्ष रखते हुए मंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच यह मुद्दा बीते 26 वर्षों से विवाद का कारण बना हुआ था। उन्होंने बताया कि वाणसागर समझौता 1973 में हुआ था, तब सोन नदी के जल को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच विवाद था, लेकिन 2000 में बिहार के विभाजन के बाद झारखंड भी अपना हिस्सा मांगने लगा। मंत्री ने कहा कि झारखंड बिहार के कोटे के पानी में हिस्सेदारी चाहता था। उन्होंने कहा कि इस तरह 53 वर्ष पहले समझौता हुआ, लेकिन जल बंटवारा अब संभव हो पाया है। उन्होंने बताया कि 36 वर्ष पहले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भी सौंप दी गई थी, लेकिन इसका कार्यान्वयन अब हो सकेगा। चौधरी ने कहा कि पिछले वर्ष रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बिहार ने सोन नदी जल बंटवारे का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि इसके बाद केंद्र सरकार के हस्तक्षेप और झारखंड के सकारात्मक रुख के कारण दोनों राज्यों के बीच औपचारिक सहमति बन गई। उन्होंने बताया कि हाल में झारखंड ने जल बंटवारे के फार्मूले पर अपनी सहमति दे दी है जिसके तहत सोन नदी के कुल 77.5 करोड़ एकड़ फीट (एमएएफ) पानी में से बिहार को 57.5 करोड़ एकड़ फीट और झारखंड को दो एमएएफ पानी मिलेगा। रोहतास जिले में इंद्रपुरी बैराज से लगभग 80 किलोमीटर दूर मटिआंव में इंद्रपुरी जलाशय (पुराना नाम कदवन जलाशय) का निर्माण प्रस्तावित है। इस संबंध में 1990 में डीपीआर केंद्रीय जल आयोग को सौंपी गई थी। हालांकि, बांध के 173 मीटर पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) पर उत्तर प्रदेश ने आपत्ति जताई थी।

उत्तर प्रदेश का कहना था कि इससे ओबरा पनबिजलीघर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता, इसलिए उसने सहमति नहीं दी।

खराब प्रदर्शन और डोपिंग के कारण एक हजार से अधिक खिलाड़ी खेलो इंडिया से बाहर : मनसुख मांडविया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। खेलमंत्री मनसुख मांडविया ने बृहस्पतिवार को कहा कि पिछले तीन साल में खराब प्रदर्शन या डोपिंग के कारण से विभिन्न खेलों के 1342 खिलाड़ियों को खेलो इंडिया कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया है।

खेलो इंडिया में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के ब्यौरे को लेकर राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में मनसुख मांडविया ने कहा कि इसी दौरान 2905 नए खिलाड़ियों को भी योजना में शामिल किया गया ।

उन्होंने कहा ,'' पिछले तीन साल में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाने या डोपिंग के मामलों के कारण 1342 खिलाड़ियों को कार्यक्रम से

बाहर किया गया । प्रदर्शन की समीक्षा हर साल की जाती है और समय समय पर खेलो इंडिया की वेबसाइट पर डाला जाता है ।''

खेलमंत्री ने कहा कि 23000 से अधिक खिलाड़ियों को खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण और सहयोग दिया जा रहा है ।

डोपिंग निरोधक उपायों से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी (नाडा) को मजबूत बनाने के लिए सीबीआई जैसी एजेंसियों को जोड़ा गया है । उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित दवाओं के गलत इस्तेमाल और तस्करी से निपटने के लिए सीबीआई और कानून का पालन कराने वाली अन्य एजेंसियों से तालमेल को भी बढावा दिया जा रहा है ।

भारत पिछले तीन साल में प्रतिबंधित दवाओं के इस्तेमाल की पाजिटिविटी दर के मामले में विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी (वाडा) की सूची में शीर्ष पर है ।

सुविचार

जब जिंदगी के पन्नों पर भगवान की कलम चलती है तो वह भी हो जाता है जो इंसान कभी सोचता भी नहीं।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

अंधविश्वास का खतरनाक खेल

दिल्ली पुलिस ने धनवर्षा का झांसा देकर जहरीले लड्डू खिलाने वाले एक कथित तांत्रिक का पर्दाफाश कर सराहनीय कार्य किया है। इस शख्स पर तीन लोगों की हत्या का आरोप है। इसके अपराधों की सूची यहीं तक सीमित नहीं है। इसके खिलाफ राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी गंभीर मामले दर्ज हैं। ऐसे पाखंडियों का धंधा इसलिए फल-फूल रहा है, क्योंकि उन्हें शिकार आसानी से मिल जाते हैं। लोग 21वीं सदी में इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि कोई कथित तांत्रिक अपनी क्रियाओं से धन बरसा देगा! जिसमें थोड़ी भी बुद्धि होगी, वह जरूर सोचेगा- अगर कोई शख्स सच में इतना करामाती है तो वह अपने लिए धन क्यों नहीं बरसा लेता? उसकी ऐसी क्या मजबूरी है कि वह दूसरों के लिए धन बरसाता है? अगर किसी के पास ऐसी शक्ति आ जाए कि वह एक इशारा करे और आकाश से सोने-चांदी की ईंटें बरसने लगें तो वह दूसरों को बताने की गलती कभी नहीं करेगा, बल्कि अपना भंडार भरेगा। क्या लोगों में इतनी भी समझ नहीं है? जब लालच का पर्दा पड़ता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसे पाखंडियों के चक्कर में वे ही लोग ज्यादा पड़ते हैं, जो तुरंत मालामाल होना चाहते हैं। सोचिए, कोई कथित तांत्रिक अपनी क्रियाओं से धन-दौलत बरसाने लगे तो क्या वह एक शहर से दूसरे शहर मारा-मारा फिरेगा? उसे तो दुनियाभर की सरकारें मेहमान बनाकर रखेंगी और सोने-चांदी से अपने खजाने भरेंगी। वह उनके लिए सबसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति होगा। आश्चर्य तब होता है, जब उच्च शिक्षित लोग ऐसे पाखंडियों के जाल में फंस जाते हैं।

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इतिहास ऐसे ठगों के किस्सों से भरा पड़ा है। ये सदियों से भोले-भाले लोगों को लूटकर अपना उल्लू सीधा करते आए हैं। इन्हें कभी निराश नहीं होना पड़ता। इनके लिए 'रोजगार' की कोई कमी नहीं है। ये बीस-पच्चीस लोगों पर जाल फेंकते हैं तो दो-चार जरूर फंस जाते हैं। उनसे इतनी कमाई हो जाती है कि खुद ठाठ से ज़िंदगी जीते हैं। इसके बाद फिर किसी नए शिकार की तलाश करते हैं। कुछ कथित तांत्रिक सोशल मीडिया पर दावा करते हैं कि उनकी शरण में आने से जमीन में गड़ा हुआ धन सपने में दिखाई देगा! अगर ऐसा सच में होता तो वे खुद ही सपने देखकर अरबपति क्यों नहीं बन जाते? उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस, दिन-रात सपने देखते रहें। इन दिनों एक और दावा खूब किया जा रहा है- 'लोगों को अपने वश में करें!' यह पहले भी बहुत किया जाता था। अक्सर लोग उनके पास जाकर अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को वश में करने का आग्रह करते हैं। कई माता-पिता अपनी संतानों को, बहू अपने सास-ससुर को, सास-ससुर अपने बेटे-बहू को, कर्मचारी अपने बॉस को, अविवाहित लोग अपने मनपसंद व्यक्ति को वश में करने के लिए उनके द्वार पर माथा टेकते हैं। इससे कोई वश में नहीं होता, बल्कि कथित तांत्रिक जरूर मालामाल होता है। वह तरह-तरह की चीजों और क्रियाओं के नाम पर जमकर रुपए वसूलता है। अगर यूं ही किसी को वश में करना संभव होता तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन को वश में कर युद्ध बंद करवा चुके होते। इमरान ख़ान (जिनके काला जादू करने के किस्से मशहूर हैं) के जेल जाने की नौबत न आती। वे पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को वश में कर आज अपने देश के प्रधानमंत्री होते। डोनाल्ड ट्रंप, जो नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए लगातार झूठे दावे कर रहे हैं, इसकी चयन समिति के सदस्यों के मन पर कब्जा कर अब तक 'शांति पुरुष' की उपाधि प्राप्त कर लेते। इसलिए ऐसे झूठे दावों पर बिल्कुल विश्वास न करें। विवेक से काम लें। अपने समय, श्रम, धन और जीवन को बर्बाद न करें।

ट्वीटर टॉक

वैदिक चेतना के महान उद्घोषक एवं आध्यात्मिक चिंतक, आर्य समाज के संस्थापक, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। असीम ज्ञान और उच्च गुणों से सम्पन्न स्वामी जी का सम्पूर्ण जीवन समाज-उत्थान, राष्ट्र-जागरण और मानव-कल्याण के पावन कार्यों में बीता।

-योगी आदित्यनाथ

राजस्थान का समग्र और सर्वांगीण विकास ही हमारी सरकार का एकमात्र लक्ष्य और संकल्प है। वर्ष 2026-27 के बजट का आकार 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपये है, जो वर्ष 2023-24 के बजट की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है।

-भजनलाल शर्मा

नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले लेबर कोड लाकर मजदूरों के अधिकारों पर हमला किया, फिर अमेरिका के दबाव में किसानों के हितों से समझौता कर लिया। अमेरिकी ट्रेड डील में जिस तरह की शर्तें रखी गई हैं, उससे भारतीय किसानों की कमर टूट जाएगी।

-प्रियंका गांधी वाड्रा

प्रेरक प्रसंग

शांति का रहस्य

एक नगर में महात्मा कबीर ठहरे हुए थे। वे साधारण वस्त्र पहनते थे, लेकिन उनके वचन अत्यंत गहरे और प्रभावशाली होते थे। एक दिन एक धनी व्यक्ति कबीर के पास आया और बोला'महात्मा जी, मेरे पास धन, प्रतिष्ठा और सुविधाएं सब कुछ हैं, फिर भी मन अशांत रहता है। मुझे शांति कैसे मिले?' कबीर मुस्कराए और बोले'तुम्हारे पास सब कुछ है, पर तुम स्वयं अपने पास नहीं हो।' यह सुनकर वह व्यक्ति चकित रह गया। कबीर ने पास रखी मिट्टी की एक हांडी उठाई और कहा'इसे सोने से भर दो।' व्यक्ति ने हांडी को सोने से भर दिया। फिर कबीर ने पूछा'अब इसमें और कुछ समा सकता है क्या?' वह बोलानहीं। तब कबीर ने कहा'बस, यही तुम्हारी समस्या है। जब मन अहंकार, लोभ और संग्रह से भरा हो, तो शांति के लिए स्थान कहां बचेगा?' यह सुनकर उस व्यक्ति का सिर झुक गया। उसे समझ आ गया कि अशांति का कारण बाहर नहीं, उसके भीतर है। उसने अपने अहंकार को छोड़ने का संकल्प लिया। कबीर ने अंत में कहा'जब मन खाली होता है, तभी उसमें सत्य और शांति का वास होता है।'

सामयिक

आगामी ई-समिट और भारत के इंडिया एआई मिशन' के संदर्भ में यह और भी प्रासंगिक हो जाता है कि तकनीक का विकास पारदर्शिता, शुद्धता और प्रमाणिकता के मूल्यों के साथ हो। यदि भारत वैश्विक एआई नेतृत्व का दावा करना चाहता है, तो उसे नैतिक मानकों की स्थापना में भी अग्रणी भूमिका निभानी होगी। केवल स्टार्टअप्स और नवाचार की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं, यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि एआई मानव गरिमा, गोपनीयता और लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करे। नियमन का उद्देश्य तकनीकी प्रगति को रोकना नहीं, बल्कि उसे उत्तरदायी बनाना होना चाहिए।

डीपफेक का धोखा और डिजिटल सख्त नियमों की अनिवार्यता

ललित गर्ग

मोबाइल : 9811051133

डिजिटल युग में सूचना की गति जितनी तीव्र हुई है, उतनी ही तेजी से भ्रम, छल और दुष्प्रचार की संभावनाएँ भी बढ़ी हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीपफेक तकनीक ने इस चुनौती को और जटिल बना दिया है। अब केवल शब्दों से नहीं, बल्कि चेहरों, आवाजों और भाव-भंगिमाओं से भी झूठ को सच की तरह प्रस्तुत किया जा सकता है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने डीपफेक और एआई जनित सामग्री के नियमन के लिए आईटी नियमों को सख्त करने का निर्णय लिया है। बीस फरवरी से लागू होने जा रहे नए प्रावधानों के अनुसार एआई द्वारा निर्मित सामग्री पर स्पष्ट लेबल लगाना अनिवार्य होगा और किसी भी अवैध या भ्रामक सामग्री को तीन घंटे के भीतर हटाना या ब्लॉक करना होगा। पहले यह समयसीमा 36 घंटे थी। यह बदलाव केवल तकनीकी संशोधन नहीं, बल्कि डिजिटल नैतिकता और लोकतांत्रिक जवाबदेही की दिशा में एक गंभीर हस्तक्षेप है।

पिछले कुछ वर्षों में डीपफेक तकनीक का दुरुपयोग भयावह रूप से सामने आया है। राजनीतिक नेताओं के फर्जी वीडियो, अभिनेत्रियों की अश्लील रूप से परिवर्तित तस्वीरें, सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाले ऑडियो क्लिप और आर्थिक धोखाधड़ी के लिए बनाए गए कृत्रिम संदेश-ये सब इस बात के प्रमाण हैं कि तकनीक तटस्थ नहीं रहती, उसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों संभव हैं। जब सत्य को जूता जा रहा हो और झूठ को परिष्कृत तकनीक के सहारे प्रमाणिकता का आवरण पहनाकर प्रस्तुत किया जा रहा हो, तब समाज में अविश्वास का वातावरण बनना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा नियंत्रण की पहल आवश्यक प्रतीत होती है, क्योंकि यह केवल अभिव्यक्ति का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की प्रतिष्ठा से जुड़ा विषय है।

नए नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से बढ़ाई गई है। अब उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उपयोगकर्ता को यह जानकारी मिले कि साझा की जा रही सामग्री एआई से निर्मित है या नहीं। इससे पारदर्शिता का एक न्यूनतम मानक स्थापित होगा। साथ ही, तीन घंटे की समयसीमा यह संकेत देती है कि सरकार डिजिटल अपराधों की गंभीरता को समझ रही है। डीपफेक वीडियो के वायरल होने के बाद उसका खंडन अक्सर प्रभावहीन हो जाता है, इसलिए त्वरित कार्रवाई ही नुकसान को सीमित कर सकती है। परंतु यह भी सच है कि इतनी कम समय सीमा में सामग्री की सत्यता की जांच करना तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत जटिल कार्य है। इससे प्लेटफॉर्मों पर निगरानी तंत्र को अत्यधिक सुदृढ़ करना पड़ेगा, जो लागत और संचालन दोनों के स्तर पर चुनौतीपूर्ण होगा।

यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि आपत्तिजनक या भ्रामक सामग्री की परिभाषा कौन और किस आधार पर तय करेगा। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मूलाधिकार है। यदि नियमन की प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायसंगत नहीं होगी, तो इसके दुरुपयोग की आशंकाएँ जन्म लेंगी। अतीत में भी यह देखा गया है कि जब-जब सोशल मीडिया पर नियंत्रण के प्रयास हुए, तब कुछ वर्गों ने इसे सरकारी अतिक्रमण के रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए नियमन और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि नियमों का प्रयोग असहमति को दबाने के लिए नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से दुष्प्रचार और अपराध को रोकने के लिए हो। इस दिशा में स्वतंत्र निगरानी तंत्र, न्यायिक समीक्षा और पारदर्शी शिकायत निवारण प्रणाली अनिवार्य घटक हो सकते हैं।

वैश्विक परिदृश्य भी इसी संकट की ओर संकेत करता है। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग की न्यूनतम आयु निर्धारित करने जैसे कदम उठाए हैं। अमेरिका में इंस्टाग्राम और यूट्यूब के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभावों की जांच के लिए ऐतिहासिक मुकदमे चल रहे हैं। वहाँ की बड़ी तकनीकी कंपनियों पर युवाओं को लत लगाने वाली संरचनाएँ विकसित करने के आरोप लगे हैं। विशेषज्ञों का मत है कि कई युवा जब अपने फोन से दूर किए जाते हैं तो वे मनोवैज्ञानिक ही नहीं, शारीरिक असहजता भी अनुभव करते हैं। यह स्थिति केवल विकसित देशों तक सीमित नहीं, भारत सहित विकासशील देशों में भी सोशल मीडिया का अनियंत्रित विस्तार सामाजिक और मानसिक संकट का कारण बन रहा है।

एआई उद्योग स्वयं भी एक नैतिक दुविधा के दौर से गुजर रहा है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में कंपनियाँ तकनीकी श्रेष्ठता की दौड़ में लगी हैं। इस दौड़ में सुरक्षा और नैतिकता के प्रश्न अक्सर पीछे छूट जाते हैं। हाल ही में एक प्रमुख कंपनी के सुरक्षा शोधकर्ता द्वारा विवादास्पद परियोजनाओं की अनियंत्रित गति पर असहमति जताते हुए त्यागपत्र देना इस तनाव का संकेत है। तकनीक की प्रगति जितनी तेज होगी, नियामक ढाँचे उतनी ही तेजी से अप्रासंगिक होते जाएँगे, यदि उन्हें समयानुकूल अद्यतन न किया जाए। इसलिए नियमन को केवल दंडात्मक नहीं, बल्कि दूरदर्शी और सहभागी होना चाहिए।

भारत के संदर्भ में यह विषय और भी संवेदनशील है। यहाँ डिजिटल क्रांति ने अभूतपूर्व विस्तार पाया है। करोड़ों नए उपयोगकर्ता प्रतिवर्ष ऑनलाइन आ रहे हैं। ऐसे में यदि असली और नकली के बीच का फर्क स्पष्ट न रहे तो लोकतांत्रिक विमर्श ही संदिग्ध हो जाएगा। चुनावी प्रक्रिया, सामाजिक सद्भाव, आर्थिक लेन-देन और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा-सभी पर डीपफेक का खतरा मंडरा सकता है। इसलिए एआई जनित सामग्री पर लेबलिंग का प्रावधान केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि सूचना साक्षरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। परंतु यह भी ध्यान रखना होगा कि लेबलिंग तभी प्रभावी होगी जब आम उपयोगकर्ता डिजिटल साक्षर हो। अन्यथा वह लेबल को समझे बिना ही सामग्री साझा करता रहेगा।

आगामी ई-समिट और भारत के इंडिया एआई मिशन' के संदर्भ में यह और भी प्रासंगिक हो जाता है कि तकनीक का विकास पारदर्शिता, शुद्धता और प्रमाणिकता के मूल्यों के साथ हो। यदि भारत वैश्विक एआई नेतृत्व का दावा करना चाहता है, तो उसे नैतिक मानकों की स्थापना में भी अग्रणी भूमिका निभानी होगी। केवल स्टार्टअप्स और नवाचार की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं, यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि एआई मानव गरिमा, गोपनीयता और लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करे। नियमन का उद्देश्य तकनीकी प्रगति को रोकना नहीं, बल्कि उसे उत्तरदायी बनाना होना चाहिए।

अंततः यह समझना होगा कि डीपफेक और एआई का संकट केवल तकनीकी नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक भी है। कानून आवश्यक है, परंतु पर्याप्त नहीं। डिजिटल कंपनियों की जवाबदेही, सरकार की पारदर्शिता, न्यायपालिका की सतर्कता और नागरिकों की जागरूकता-इन सबका समन्वय ही इस चुनौती का स्थायी समाधान दे सकता है। यदि नियमन संतुलित और निष्पक्ष होगा तो वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने के बजाय उसे सुरक्षित करेगा, क्योंकि स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब वह सत्य और जिम्मेदारी के साथ जुड़ी हो। झूठ को सच में बदलने की तकनीकी क्षमता जितनी बढ़ रही है, उतनी ही दृढ़ता से सत्य की रक्षा के लिए सामूहिक संकल्प भी आवश्यक है। यही डिजिटल युग की सबसे बड़ी नैतिक परीक्षा है, और यही लोकतांत्रिक समाज की अगली कसौटी भी।

नजरिया

पाखंड की ओट में छुपा दान : क्या यह सच में पुण्य है?

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

मोबाइल : 94251 23883

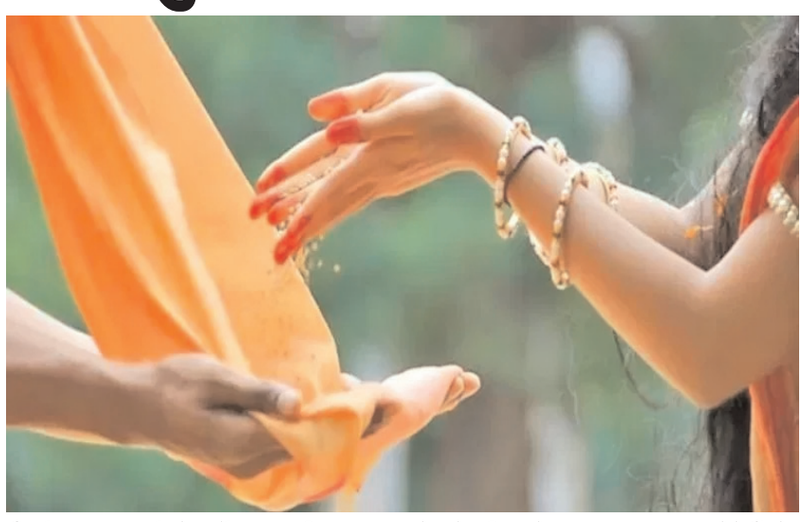

मनुष्य की आत्मा जब अपने कर्मों का निष्पक्ष लेखा-जोखा करती है, तब सबसे पहले यह प्रश्न उसके अंतर्मन में गूँजता है-क्या धन की पवित्रता से बड़ा कोई नैतिक मूल्य हो सकता है? आज के युग में, जब अनेक लोग छल, कपट और अनैतिक तरीकों से अर्जित धन को धार्मिक कार्यों में लगाकर स्वयं को धर्मात्मा सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, तब इस प्रवृत्ति की गंभीर समीक्षा अनिवार्य हो जाती है। यह विषय केवल दान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चरित्र, विवेक और सामाजिक उत्तरदायित्व की कसौटी है। भव्य मंदिर, विशाल दानशालाएँ और चमकदार आयोजन हमारी आँखों को चकाचौंध कर सकते हैं, किंतु उनके पीछे छिपा अन्याय प्रायः दृष्टि से ओझल रह जाता है। यही भ्रम धीरे-धीरे हमारी चेतना को शिथिल करता है और हमें नैतिक पतन की खाई की ओर धकेल देता है।

अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गलत कमाई को अच्छे कार्यों में लगा रहा है, तो कम से कम वह समाज का हित तो कर ही रहा है। परंतु यह सोच न केवल सतही है, बल्कि अत्यंत भ्रामक भी है। जिस धन की नींव शोषण, धोखा और भ्रष्टाचार पर रखी गई हो, वह कभी भी सच्चे कल्याण का माध्यम नहीं बन सकता। ऐसा धन पीड़ितों की आहों, आँसुओं और असहनीय पीड़ा से जुड़ा होता है। जब उसी धन से दान किया जाता है, तब वह सहायता नहीं, बल्कि अन्याय का एक नया रूप बन जाता है-अन्याय का पुनर्वितरण। समाज को यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि सच्ची भलाई का मार्ग केवल शुद्ध और न्यायपूर्ण साधनों से होकर ही गुजरता है।

भारतीय दर्शन सदैव साधन और साध्य-दोनों की शुद्धता पर बल देता आया है। उपनिषद, गीता और स्मृतियाँ एक स्वर में यह उद्घोष करती हैं कि अधर्म से अर्जित धन कभी भी पुण्य का स्रोत नहीं बन सकता। श्रीमद्भगवद्गीता में सात्त्विक, राजस और तामस दान का विवेचन करते हुए शुद्ध भावना और ईमानदार कमाई को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। मनुस्मृति भी यही प्रतिपादित करती है कि अन्यायपूर्ण साधनों से प्राप्त संपत्ति आत्मिक उन्नति में बाधक बनती है। वास्तव में धर्म का उद्देश्य मनुष्य को नैतिक ऊँचाइयों तक पहुँचाना है, न कि उसे अपने पापों पर आडंबर का आवरण चढ़ाने की अनुमति देना। इतिहास स्वयं इस निर्विवाद सत्य का साक्षी है कि अपराध और दान का संगम कभी भी महानता की रचना नहीं कर सका। अनेक शासकों और धनाढ्य व्यक्तियों ने अस्पताल, विद्यालय और धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया, परंतु उनके अत्याचार, अन्याय और निर्दयता उन्हें कभी महान नहीं बना सके। जनता के खून-पसीने और पीड़ा से अर्जित धन से खड़े किए गए भवन केवल निर्जीव पत्थर के ढाँचे होते हैं, जिनमें नैतिकता और संवेदनशीलता की आत्मा का सर्वथा अभाव होता है। समय ने बार-बार यह सिद्ध किया है कि व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उसके आचरण और कर्मों से आँका जाता है, न कि उसके दान की भव्यता और राशि से।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी गलत कमाई से किया गया दान आत्म-शुद्धि का एक झूठा भ्रम उत्पन्न करता है। अनेक लोग इसे अपने अपराध-बोध से मुक्ति पाने का सरल उपाय मान लेते हैं। वे यह मान बैठते हैं कि कुछ धन दान कर देने मात्र से उनके पाप धुल जाएँगे और उनका अंतर्मन निर्मल हो जाएगा। किंतु यह मानसिकता आत्म-सुधार नहीं, बल्कि आत्म-छल और आत्म-प्रवंचना का रूप है। सच्चा प्रायश्चित तभी संभव होता है, जब मनुष्य अपने गलत मार्ग को त्यागकर सत्य, ईमानदारी और नैतिकता के पथ पर दृढ़ता से अग्रसर हो। बिना आचरण बदले किया गया दान आत्मा को अस्थायी संतोष देने वाला एक छलावा मात्र बनकर रह जाता है।समाज पर इस प्रवृत्ति का प्रभाव अत्यंत गहरा और चिंताजनक होता है। जब बेईमान लोग बड़े-बड़े दानों के माध्यम से सम्मान, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त कर लेते हैं, तब ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति स्वयं को उपेक्षित और हताश अनुभव करता है। इससे समाज का नैतिक संतुलन डगमगाने लगता है और युवाओं को यह गलत संदेश मिलने लगता है कि सफलता का मार्ग सत्य और परिश्रम से नहीं, बल्कि चतुराई, छल और अनैतिकता से होकर जाता है। धीरे-धीरे यही सोच पूरे सामाजिक ताने-बाने को खोखला कर देती है और परस्पर विश्वास की नींव को गहराई से हिला देती है।

वास्तव में सच्चा दान वही होता है, जो त्याग, करुणा और पवित्र परिश्रम की भूमि पर अंकुरित होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी सीमित आय और साधनों के बावजूद दूसरों की पीड़ा को समझकर सहायता के लिए हाथ बढ़ाता है, तब उसका योगदान आकार में छोटा होकर भी मूल्य में महान बन जाता है। उसमें अहंकार का प्रदर्शन नहीं, बल्कि निःस्वार्थ सेवा की भावना होती है। ऐसा दान समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है और नैतिक मूल्यों की जड़ों को और अधिक सुदृढ़ करता है। इसके विपरीत, गलत कमाई से किया गया दान प्रायः दिखावे, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की अतृप्त लालसा से प्रेरित होता है, जिसमें संवेदना से अधिक स्वार्थ छिपा होता है।

समाधान का मार्ग पूर्णतः स्पष्ट और निर्विवाद है। हमें दान की मात्रा और भव्यता से अधिक उसके स्रोत और भावना की शुद्धता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। समाज का दायित्व है कि वह भ्रष्टाचार और अनैतिकता से अर्जित धन को सम्मान देने के बजाय ईमानदार, परिश्रमी और सत्यनिष्ठ जीवन को सर्वोच्च आदर्श के रूप में स्थापित करे। शिक्षण संस्थानों, धार्मिक संगठनों और मीडिया को भी इस विषय पर निरंतर जागरूकता फैलाकर लोगों की सोच को सही दिशा देनी चाहिए। जब हम संपत्ति से ऊपर चरित्र को स्थान देंगे, तभी सच्चे अर्थों में एक न्यायपूर्ण, संवेदनशील और नैतिक समाज का निर्माण संभव हो सकेगा।

यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि गलत तरीकों से कमाए गए धन से किया गया दान पुण्य नहीं, बल्कि अन्याय और पाप पर चढ़ाया गया एक चमकदार आवरण मात्र है। यह समाज को भ्रमित करता है, सत्य को ढक देता है और नैतिक मूल्यों को धीरे-धीरे क्षीण कर देता है। सच्ची धार्मिकता मंदिरों, मस्जिदों या दानपेटियों की सीमाओं में नहीं, बल्कि ईमानदार जीवन, अडिग सत्यनिष्ठा और करुणामय आचरण में निवास करती है। हमें इतना साहस अवश्य दिखाना होगा कि हम ऐसे दिखावटी दान की प्रशंसा करने से इंकार करें और स्पष्ट शब्दों में यह घोषित करें-पुण्य का मार्ग केवल शुद्ध, न्यायपूर्ण और नैतिक साधनों से होकर ही जाता है।

महत्त्वपूर्ण

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**, (*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- **दक्षिण भारत राष्ट्रमत**

अवार्ड

मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह गुरुवार को इंफाल के सिटी कन्वेंशन सेंटर में नेशनल रोड सेफ्टी मंथ ऑब्जर्वेशन 2026 के ग्रैंड फिनाले के दौरान मैराथन और पेंटिंग कॉम्पिटिशन के विजेता को अवॉर्ड देते हुए।

पेरू अपनी संप्रभुता चीन से खो सकता है : अमेरिका की चेतावनी

लीमा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने चिंता जताई है कि चीन लातिन अमेरिकी देश पेरू के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर अपना नियंत्रण मजबूत करके उसकी संप्रभुता को नुकसान पहुंचा रहा है।अमेरिकी की यह चेतावनी पेरू की एक अदालत के उस फैसले के बाद आई है जिसमें एक स्थानीय नियामक ने चीन द्वारा बनाए गए विशाल बंदरगाह की निगरानी को सीमित कर दिया है। पेरू की राजधानी लीमा के उत्तर में चांकाय में स्थित 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से स्थापित गहरे पानी का बंदरगाह लातिन अमेरिका में चीन की पकड़ का प्रतीक बन गया है। यह बंदरगाह अमेरिका के साथ तनाव का केंद्र बिंदु भी है।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के पश्चिमी गोलार्ध मामलों के ब्यूरो ने सोशल मीडिया मंच पर कहा कि वह उन नवीनतम खबरों से चिंतित है कि पेरू अपने सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक, चांकाय पर नजर रखने में असहाय हो सकता है, जो लालची चीनी मालिकों के अधिकार क्षेत्र में है।

अमेरिका ने कहा, हम पेरू के उसके क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की देखरेख करने के संप्रभु अधिकार का समर्थन करते हैं। इसे इस क्षेत्र और दुनिया के लिए एक सबक के रूप में लें, सस्ते चीनी ऋण की कीमत संप्रभुता से चुकानी पड़ती है। यह चिंता ऐसे समय में सामने आई है जब ट्रंप प्रशासन पश्चिमी गोलार्ध पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। वहीं, चीन लंबे समय से बड़े पैमाने पर ऋण और व्यापार के माध्यम से अपना प्रभाव स्थापित कर रहा है।चीन की सरकार ने बृहस्पतिवार को अमेरिकी टिप्पणियों को सिरे से खारिज कर दिया है।

प्रदर्शन

नागपुर में गुरुवार को मज़दूर संगठन संयुक्त कृति के कर्मचारियों ने नागपुर में केंद्र और राज्य सरकारों की कथित मज़दूर-विरोधी, किसान-विरोधी और जनता-विरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल के दौरान विरोध प्रदर्शन किया।

बांग्लादेश में हिंदू चाय बागान मजूदर की हत्या

ढाका/भाषा। पूर्वोत्तर बांग्लादेश के मौलवीबाजार इलाके में एक युवा हिंदू चाय बागान मजदूर का खून से लथपथ शव मिला है और उसके हाथ-पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। स्थानीय मीडिया ने बृहस्पतिवार को यह खबर दी।

बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को मतदान से पहले, यह लगातार दूसरे दिन किसी हिंदू व्यक्ति की हत्या किए जाने का मामला है।

पुलिस ने बुधवार को ढाका से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित मौलवीबाजार के कमलगांज उपजिले के एक चाय बागान से 28 वर्षीय रतन शुवो कार का शव बरामद किया।

' द डेली स्टार' ने कमलगांज पुलिस थाने के प्रभारी अब्दुल अवाल के हवाले से खबर दी कि मृतक रतन शुवो कार इस्लामपुर यूनियन के अंतर्गत चंपारा चाय बागान में बतौर मजदूर काम करता था। खबर के मुताबिक स्थानीय लोगों ने बुधवार पूर्वाह्न करीब 10:00 बजे बागान में शव को देखा और अधिकारियों को सूचना दी।

स्थानीय लोगों के मुताबिक शव पर चोट के स्पष्ट निशान थे और वह खून से लथपथ था।

रतन के बड़े भाई लक्ष्मण कार ने बताया कि परिवार मंगलवार रात से ही उसकी तलाश कर रहा था। उन्होंने बताया, बुधवार सुबह हमें सूचना मिली कि उसका शव बागान में पड़ा है। हम वहां गए और उसकी पहचान की। हमें नहीं पता कि उसकी हत्या क्यों की गई।

थानाधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मौलवीबाजार सदर अस्पताल भेजा गया है और हत्या में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।'द डेली स्टार' के अनुसार, कुछ स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि हत्या बृहस्पतिवार के मतदान से जुड़ी हो सकती है। हालांकि, इस संबंध में कोई सबूत नहीं मिला।

दिसंबर में कट्टरपंथी युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद से बांग्लादेश में हिंदू आबादी को कई हमलों का सामना करना पड़ा है। इनमें से कुछ हमले जानलेवा साबित हुए हैं।

मेमनसिंह जिले के त्रिशाल उपजिले के बोगर बाजार चौराहे पर सोमवार को 62 वर्षीय हिंदू व्यापारी सुसेन चंद्र सरकार की उनकी दुकान के भीतर ही कुछ अज्ञात लोगों ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी।

पुलिस ने बताया कि 'भाई भाई एंटरप्राइज' के मालिक सरकार साउथकंडा गांव के निवासी थे। उसके मुताबिक हमलावरों ने उन पर धारदार हथियार से हमला किया और शव को दुकान में छोड़कर बाहर से शटर बंद कर दिया था।

नई दिल्ली में संसद के बजट सत्र के दौरान संसद भवन परिसर में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव।

होटल बुकिंग नहीं, पाकिस्तानी हॉकी खिलाड़ियों ने सड़क पर गुजारे कई घंटे

कराची/भाषा। पाकिस्तान हॉकी टीम के सदस्यों को कैनबरा पहुंचने पर कई घंटे सड़क पर बिताने पड़े क्योंकि धन के अभाव में पाकिस्तान हॉकी महासंघ होटल के बिल का भुगतान नहीं कर सका जिससे होटल बुकिंग रद्द हो गई ।

पाकिस्तानी टीम होबर्ट में एफआईएच प्रो लीग के दूसरे चरण के मैच खेलने आस्ट्रेलिया में है । टीम के सूत्रों के अनुसार खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों को घंटों तक सड़क पर रहना पड़ा । एक सूत्र ने बताया , खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए कैनबरा में एक चार सितारा होटल में कमरे बुक किए गए थे । उन्हें बताया गया था कि पाकिस्तान खेल बोर्ड और पीएचएफ ने कैनबरा में उनके रहने के लिए सारे भुगतान कर दिए हैं ।

सूत्र ने कहा , लेकिन पिछले सप्ताह कैनबरा पहुंचने पर पता चला कि उस होटल में कोई बुकिंग थी ही नहीं । टीम के मुख्य कोच ताहिर जमान टाइम जोन अलग होने के कारण पीएसबी और पीएचएफ अधिकारियों से संपर्क नहीं कर सके । सूत्र ने कहा , ताहिर ने उन्हें इस स्थिति के बारे में बताया कि लाहौर से लंबा सफर करके आये खिलाड़ियों के पास आराम करने की कोई जगह नहीं है । हॉकी पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है और टीम प्रो लीग में आस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसी शीर्ष टीमों से खेल रही है ।

सूत्र ने बताया कि कई घंटे बाहर इंतजार करने के बाद होटल प्रबंधन ने खिलाड़ियों को कुछ कमरे दिए । सूत्र ने कहा , कमरे उपलब्ध नहीं थे लिहाजा एक ही कमरे में दो तीन खिलाड़ी रूके और अगले दिन आस्ट्रेलिया से मैच खेलने स्टेडियम गए जिसमें 2 . 3 से पराजय मिली । इससे पहले अर्जेंटीना में प्रो लीग के पहले चरण में खिलाड़ियों को दैनिक भत्ते नहीं मिले थे जिससे विदेश में उन्हें पैसों की किल्लत हो गई । कैनबरा में टीम मैनेजर के बिना गई है क्योंकि नियमित मैनेजर और पूर्व ओलंपियन अंजुम सईद को पीएचएफ ने निकाल दिया है ।उन्हें वापिस लौटते समय फ्लाइट में सिगरेट पीते पाया गया और हवाई अड्डे पर सुरक्षा अधिकारियों से उनकी झड़प भी हुई । सूत्र ने बताया कि कैनबरा में कुछ स्थानीय पाकिस्तानी लोगों से संपर्क किया गया जिन्होंने आकर उनकी मदद की । पाकिस्तान प्रो लीग के सभी छह मैच हार चुका है।

सिद्धांत चतुर्वेदी ने 'दो दीवाने सहर में' के साथ शुरू किया अपना सफर

मुंबई/एजेन्सी

सिद्धांत चतुर्वेदी अपने सिनेमाई सफर के एक नए अध्याय में कदम रख रहे हैं, जहां वह पहली बार पूरी तरह से रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते नजर आनेवाले हैं। फिलहाल फिल्म 'दो दीवाने सहर में' के जरिए वह अपने अब तक के इंटेंस और लेयर्ड किरदारों से अलग, संवेदनशील, आकर्षक और भावनात्मक अंदाज में दिखाई देंगे। कई लोग इसे उनका 'लवर बॉय एरा' भी कह रहे हैं। संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म के साथ सिद्धांत एक ऐसे सिनेमा जगत में प्रवेश कर रहे हैं,

जहां उन्हें 'भंसाली हीरो' की पहचान मिल रही है।

ये वो दुनिया है, जहां प्रेम काव्यात्मक होता है, भावनाएं गहरी होती हैं और कहानी कहने के कई अंदाज होते हैं। ये कहें तो गलत नहीं होगा कि भंसाली से जुड़ा प्रोजेक्ट अपने आप में एक विरासत और भव्यता का प्रतीक माना जाता है, और इस जोन में सिद्धांत का आना उनके करियर के विस्तार और विकास का संकेत देता है। गौरतलब है कि फिल्म में पहली बार उनकी जोड़ी मृणाल ठाकुर के साथ बनी है, जो फिल्म की ताजगी को और भी खास बनाती है। फिलहाल दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को लेकर शुरुआती झलकियों ने ही दर्शकों में उत्सुकता बढ़ा दी है और सिद्धांत को रोमांटिक हीरो के तौर पर स्थापित कर दिया है। ऐसे में यह कहें तो गलत नहीं होगा कि 20 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही फिल्म 'दो दीवाने सहर में' से भंसाली हीरो के तौर पर सिद्धांत चतुर्वेदी की जगह पूरी तरह से पक्की हो गई है।

चेक बाउंस केसः राजपाल यादव को नहीं मिली जमानत

नई दिल्ली/एजेन्सी

बॉलीवुड के जाने-माने कॉमेडियन और अभिनेता राजपाल यादव लंबे समय से चल रहे चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी जमानत याचिका पर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत देने से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने मुरली प्रोजेक्ट कंपनी को नोटिस जारी किया। अभिनेता राजपाल यादव ने शाहजहांपुर जाकर अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत की अपील की है, लेकिन कोर्ट ने अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं दिया है। राजपाल यादव के वकील भाष्कर उपाध्याय ने बताया कि जमानत की सुनवाई को फिलहाल टालने का कारण यह है कि उन्हें दूसरी पार्टी को जवाब देना है।वकील ने कहा कि जेल में जाकर राजपाल यादव से मिलने के बाद ही वे भुगतान संबंधी निर्देश प्राप्त करेंगे। जो पैसा पांच करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के रूप में लगाया गया था, उसे देने से अभिनेता ने कभी इनकार नहीं किया। पहले भी जब भुगतान की चर्चा हुई थी, तब कंपनी ने पैसे लेने से मना किया था।

भाष्कर उपाध्याय ने बताया कि 2012 के एग्रीमेंट के आधार पर मामला चल रहा है। इस दौरान राजपाल यादव ने पहले से ही तीन महीने की सजा काट ली है। राजपाल यादव को पैसे किसने दिए? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि यह पारिवारिक मामला है।उन्होंने कहा कि फिलहाल पांच करोड़ में से ढाई करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है और सोमवार को कोर्ट में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दरअसल, राजपाल यादव ने 2010 में अपनी डायरेक्टोरियल फिल्म 'अता-पता लापता' बनाने के लिए मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से लगभग पांच करोड़ रुपए का लोन लिया था। फिल्म आर्थिक रूप से सफल नहीं हुई, जिससे भुगतान में देरी हुई और कई चेक बाउंस हो गए।

मधुर भंडारकर की 'द वाइव्स' में 'महक' बनेंगी मौनी रॉय

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेत्री मौनी रॉय निर्देशक मधुर भंडारकर की आगामी फिल्म 'द वाइव्स' में नजर आएंगी। इस फिल्म की शूटिंग हाल ही में पूरी हो गई है। बुधवार को मौनी रॉय ने इंस्टाग्राम के जरिए इस बात की जानकारी दी। फिल्म में मौनी रॉय 'महक' नाम का किरदार निभा रही हैं। अभिनेत्री ने बताया कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है और निर्देशक मधुर भंडारकर के साथ काम करना उनकी बकेट लिस्ट का एक अहम हिस्सा था। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर फिल्म की बीटीएस तस्वीरें शेयर कीं। इसमें मौनी के साथ-साथ फिल्म के बाकी कलाकार और मधुर भंडारकर भी नजर आ रहे हैं। मौनी ने लिखा, शानदार फिल्म 'द वाइव्स' की मैंने शूटिंग पूरी कर ली है। यह मेरी जिंदगी की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक बनने वाली है। मधुर भंडारकर सर का बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे यह किरदार दिया। आपके साथ काम करना मेरी बकेट लिस्ट का अहम हिस्सा था।इसी के साथ ही मौनी ने अपने सह-कलाकारों की भी तारीफ की। उन्होंने लिखा, मेरे शानदार को-स्टार्स का भी शुक्रिया, जो बहुत दयालु, प्यारे और सहयोगी रहे। फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

निर्माता-निर्देशक मधुर भंडारकर आगामी फिल्म 'द वाइव्स' के जरिए सेलेब्स की पत्नियों की कहानी को पर्दे पर लेकर आ रहे हैं। फिल्म में बॉलीवुड की महिलाओं के ग्लैमर के पीछे छिपी जिंदगी से जुड़ी कहानी को दिखाया जाएगा। इसमें मौनी के अलावा, सोनाली कुलकर्णी, रेजिना कैसंड्रा, राहुल भट्ट, सौरभ सचदेवा, अर्जन बाजवा और फ्रेडी दारूवाला जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। इसके अलावा, फिल्म में अन्य कलाकार भी नजर आएंगे, लेकिन अभी उनके बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। मेकर्स ने रिलीज की तारीख अनाउंस नहीं की है। इसके अलावा, मौनी आगामी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज 'अब होगा हिसाब' में नजर आएंगी। इस सीरीज में मौनी रॉय, शाहीर शेख और निमृत कौर अहलूवालिया भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। हालांकि, मेकर्स ने सीरीज के रिलीज डेट की घोषणा अभी तक नहीं की।

संसद में स्थापित सेंगोल से है फिल्म स्वयंभू का खास कनेक्शन, अभिनेता निखिल ने किया बड़ा खुलासा

मुंबई/एजेन्सी

साउथ सिनेमा की आगामी पीरियड ड्रामा फिल्म 'स्वयंभू' जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी। भारत कृष्णमाचारी द्वारा निर्देशित, यह फिल्म साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है, जिसमें निखिल के साथ अभिनेत्री संयुक्ता और नभा नटेश मुख्य भूमिकाओं में हैं। अभिनेता निखिल ने हाल ही में फिल्म को लेकर खुलासा किया। उन्होंने बताया कि फिल्म 'स्वयंभू' की कहानी प्राचीन प्रतीक सेंगोल से प्रेरित है।

सेंगोल धर्मपूर्ण शासन, न्याय और नैतिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। निखिल ने कहा, फिल्म 'स्वंयभू' भारतीय इतिहास के एक बहुत ही खास पहलू से ली गई है, जो सेंगोल का इतिहास है। अभिनेता ने बताया कि सभी लोग सेंगोल को मुख्य रूप से प्राचीन राजदंड के रूप में जानते हैं, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन के उद्घाटन के दौरान अपने साथ ले गए थे और वहां स्थापित किया था, लेकिन इसके पीछे की कहानी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।

अभिनेता ने कहा, सेंगोल सबसे पहले प्रभु श्रीराम ने अपने वंशजों को दिया था। यह सही शासन, न्याय और अच्छे तरीके से राज करने की शक्ति का प्रतीक है। इस सेंगोल ने भारत के इतिहास में लंबी यात्रा की है और महान चोल वंश जैसे साम्राज्यों में इसका विशेष महत्व रहा है। हमने सेंगोल और हमारे हीरो के इर्द-गिर्द एक काल्पनिक लेकिन रोचक कहानी बनाई है।भारत कृष्णमाचारी द्वारा निर्देशित, यह फिल्म चोल साम्राज्य के दौरान एक स्वर्ण युग की स्थापना करती है, जो अपनी भव्यता के बारे में जानी जाती है। फिल्म को लेकर फैंस के मन में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं, इसका टीजर 11 फरवरी को दो शहरों में एक साथ आयोजित भव्य पैन-इंडिया इवेंट में लॉन्च किया जाएगा। फिल्म को लेकर अभी बाकी जानकारी गुप्त रखी गई है। फिल्म 'स्वयंभू' को पिक्सेल स्टूडियोज के भुवन और श्रीकर ने प्रोड्यूस किया है, जो 10 अप्रैल 2026 को दुनियाभर में रिलीज होगी।

अभिनेत्री सम्युक्ता का सबसे दमदार रूपः स्वयंभू के टीज़र में वॉरियर अवतार ने मचाया तहलका

मुंबई/एजेन्सी

अपनी पिछली फिल्मों की कामयाबी पर सवार सम्युक्ता ने स्वयंभू के टीज़र में ऐसा पावरफुल इम्पैक्ट छोड़ा है कि नज़र हटाना मुश्किल हो जाए। इस बार वो नज़र आती हैं एक भयंकर योद्धा के रूप में, जो अफरातफरी को चीरते हुए पूरे कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ती है। गूंथी हुई चोटी, युद्ध के लिए तैयार तेवर, और रफ-टफ योद्धा वेशभूषा में सम्युक्ता कच्ची ताकत और अटूट इरादे का प्रदर्शन करती दिखती हैं। उनका किरदार शब्दों से नहीं, एक्शन से बोलता है और हर फ्रेम ये इशारा देता है कि वो अपने करियर के सबसे साहसी क्रिएटिव फेज़ में कदम रख चुकी हैं। ये भूमिका इसलिए भी खास लगती है क्योंकि इससे पहले उनका परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड बेहद मजबूत रहा है। भीमला नायक में उन्होंने अपनी दमदार मौजूदगी से सबको प्रभावित किया, बिम्बिसार में पौराणिक दुनिया को एक्सप्लोर किया, विरुपाक्ष में थ्रिल का तड़का लगाया और सर में जमीन से जुड़ा अभिनय पेश किया। अब स्वयंभू में ऐसा लगता है जैसे इन सभी अनुभवों का संगम दिख रहा हो और सम्युक्ता खुद का और भी ताकतवर संस्करण बनकर सामने आई हों।

टीज़र में वो एक निडर और बेखौफ योद्धा के रूप में दिखती हैं, जो जेंडर की तय सीमाओं को चुनौती देते हुए तीखे एक्शन सीक्वेंस में कमान अपने हाथ में लेती है। कभी धनुष-बाण साधती हुई, तो कभी तलवार लहराती हुई हर सीन इस बात का सबूत है कि इस किरदार के लिए उन्होंने जबरदस्त शारीरिक ट्रेनिंग और तैयारी की है।

सम्युक्ता कहती हैं, स्वयंभू मेरे दिल के बेहद करीब है क्योंकि मैंने हमेशा ऐसे किरदार चुने हैं जो मुझे मेरे कम्फर्ट ज़ोन से बाहर ले जाएं। इस भूमिका ने मुझे शारीरिक और मानसिक, दोनों स्तर पर ऐसी चुनौती दी जैसा पहले कभी महसूस नहीं किया। एक गांव की महिला की आत्मा और शक्ति को समझने से लेकर घुड़सवारी और तीरंदाजी की कड़ी ट्रेनिंग तक, ये सफर बेहद गहन और परिवर्तनकारी रहा। इस किरदार में वो सब कुछ है जिसका एक अभिनेता सपना देखता है ताकत, संवेदनशीलता और एक मजबूत आवाज़।

इस उग्र योद्धा रूप में ढलना मेरे करियर के सबसे संतोषजनक अनुभवों में से एक रहा है। स्वयंभू के अलावा भी सम्युक्ता के पास कई दिलचस्प प्रोजेक्ट्स लाइनअप में हैं, जहां वो अपनी बढ़ती रेंज दिखाती नजर आएंगी। जल्द ही वो ब्लैक गोल्ड में एक सशक्त पुलिस अधिकारी के रूप में फिल्म को लीड करेंगी और साथ ही पुरी जगन्नाध की स्लम डॉग में विजय सेतुपति और तब्बू के साथ स्क्रीन साझा करती दिखाई देंगी।

पाकिस्तान ने चीन से अपना दूसरा स्वदेशी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्रक्षेपित किया

इस्लामाबाद/भाषा। पाकिस्तान ने चीन के यांगजियांग सीशोर प्रक्षेपण केंद्र से अपने दूसरे स्वदेशी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ईओ-2 का बृहस्पतिवार को सफल प्रक्षेपण किया। सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी।

सरकारी समाचार एजेंसी 'एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान' ने बताया कि अंतरिक्ष और ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान आयोग (एसयूपीएआरसीओ) द्वारा विकसित यह उपग्रह देश की पृथ्वी अवलोकन और उच्च-रिजॉल्यूशन इमेजिंग क्षमताओं को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। एसयूपीएआरसीओ के अधिकारियों ने बताया कि यह उपग्रह राष्ट्रीय विकास योजना, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण निगरानी और शहरी विस्तार में सहयोग देने के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इससे सटीक और समय पर उपग्रह चित्र उपलब्ध कराकर शासन, आपदा प्रबंधन, जलवायु विश्लेषण और रणनीतिक निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करने के मदद मिलेगी। अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि ईओ-2 के साथ पाकिस्तान ने अपने उपग्रह बेड़े का विस्तार किया है, जिससे पृथ्वी अवलोकन डेटा की बेहतर निरंतरता, कवरेज और सटीकता सुनिश्चित होती है। पाकिस्तान ने पिछले साल उत्तरी चीन के जियुकुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से अपना पहला स्वदेशी इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल (ईओ-1) उपग्रह प्रक्षेपित किया था।

'साधक, सर्जक, स्पष्टवादी और अनुशासन प्रिय थे अमर गुरुदेव'

13 फरवरी - पुण्यतिथि पर विशेष

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु । प्रज्ञा के जीवंत प्रतिमान आराध्य गुरुदेव, श्रुताचार्य अमरमुनिजी के संबंध में जानकारी देते हुए वरुणमुनि जी ने बताया कि उन्होंने ने अपनी निर्मल प्रज्ञा ज्योति से समस्त जिनशासन एवं सम्पूर्ण मानव जाति को आलोकित किया। उन्होंने संघ और शासन सेवा के नए आयाम स्थापित किए और स्व-पर कल्याण की नई दिशाओं को उद्घाटित किया। श्रमण संघ के ऐसे उज्ज्वल शुभ नक्षत्र का जन्म अविभाज्य भारत के क्वेटा बलूचिस्तान में भादवा सुदी पंचमी, वि.सं. 1983 (तदनुसार ई.स. 1936) को सेठ दीवानचन्द मल्होत्रा के गृह आंगन में उनकी धर्मसंगिनी बसंती देवी की कुक्षी से हुआ। विभाजन के समय अमरचन्दजी अपने माता-पिता के साथ भारत आए पर अंबाला रेलवे स्टेशन पर वे अपने माता-पिता से बिछुड़ गए। लुधियाना निवासी एक जैन श्रावक अबोध बालक को धर्म पुत्र मानकर अपने घर ले गए।

आचार्यश्री आत्मारामजी के भक्त जैन श्रावक एक दिन बालक अमर को लुधियाना के रूपा मिस्त्री गली स्थित जैन स्थानक में आचार्यश्री के दर्शनार्थ लेकर गए। उस दिन महाश्रमणीश्री सीताजी की शिष्या साध्वीश्री महेन्द्राजी का दीक्षा महोत्सव देखकर बालक 'अमर' की मनोभूमि में सुप्त विरक्ति के बीज अंकुरित हुए और वे आचार्य श्री का प्रवचन श्रवण कर संबोधि को उपलब्ध हुए। आचार्यश्री आत्मारामजी ने इस विलक्षण बालक को अपने अन्तेवासी पौत्र शिष्य भंडारी श्री पद्मचन्द्रजी म.सा. के वरदहस्त में सौंपा।

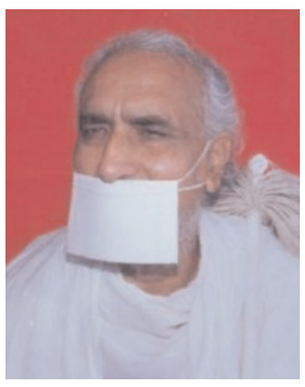

उन्होंने कहा कि इस कोहिनूर को बड़े ध्यान से तराशना, यह एक दिन जैन संस्कृति का महान नायक बनेगा। वि.सं. 2008 (तदानुसार ई. सं. 1957) भादवा सुदी पंचमी को सोनीपत मंडी (हरियाणा) में उत्तर भारतीय प्रवर्तक भंडारी श्री पद्मचन्द्रजी म.सा. के सुशिष्य के रूप में बालक अमर की जैन मुनि दीक्षा संपन्न हुई और वे 'संत श्री अमरमुनि जी' कहलाए।

गुरु के कुशल निर्देशन में अमर मुनि जी ने भारतीय एवं पाश्चात्य धर्मदर्शन का अगाध तलस्पर्शी अध्ययन किया। कुशल प्रवक्ता होने से जनमानस उन्हें वाणी के जादूगर के संबोधन से संबोधित करता था। वे साधक, सर्जक और महान संगठक होने के साथ-साथ स्पष्टवादी और अनुशासन प्रिय थे। आचार्यश्री शिवमुनिजी ने वर्ष 2004 में उन्हें 'उत्तर भारतीय प्रवर्तक' जैसे गरिमापूर्ण पद से अलंकृत किया।

अपने गुरु के नाम से आपने सैंकड़ों जन कल्याणकारी संस्थाओं की स्थापना की, जिनमें पद्म धाम, पद्म प्रकाशन (नरेला मंडी, दिल्ली), गुरु पद्म ज्ञान मंदिर (विभिन्न क्षेत्रों में), गुरु पद्म जैन आई हॉस्पिटल (पश्चिम विहार, दिल्ली), गुरु पद्म जैन सहायता कोष (विभिन्न क्षेत्रों में), गुरु पद्म जैन साधना - आराधना केन्द्र (मानसा मंडी), गुरु पद्म जैन चैरीटेबल फिजियोथैरेपी हॉस्पिटल (मंडी निहाल सिंह वाला, पंजाब व श्री गंगानगर-राजस्थान) आदि मुख्य संस्थान हैं। संयम साधना के साथ-साथ श्रुताचार्य श्री अमर मुनिजी ने सर्जन के अनेक प्रतिमान स्थापित किए और जैनागमों का सचित्र और अंग्रेजी भाषा में विश्व में सर्वप्रथम संपादन व प्रकाशन कर एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, इसके अतिरिक्त अनेक साहित्यिक कृतियों की रचना कर मां शारदा के कोष की श्रीवृद्धि भी की। अमरमुनिजी ने अनेक सुयोग्य शिष्यों को संयम रत्न प्रदान किया, जिनमें उपप्रवर्तक डॉ. सुव्रतमुनिजी, सुयोग्यमुनिजी, पंकजमुनिजी, पुनीतमुनिजी, हर्षमुनिजी, डॉ वरुणमुनिजी आदि प्रमुख हैं। वर्ष 2013 में 13 फरवरी वसंत पंचमी के दिन लुधियाना (पंजाब) में संथारा समाधि सहित सिविल लाइन जैन स्थानक में अमर मुनि जी का महाप्रयाण हुआ।

बांग्लादेश: जनमत संग्रह में 'हां' की जीत संवैधानिक निरंतरता को कर सकती बाधित : विशेषज्ञ

ढाका/भाषा

बांग्लादेश की मुहम्मद यूनुस नीत अंतरिम सरकार की ओर से जटिल सुधार के लिए कराए जा रहे जनमत संग्रह को जनता की सहमति मिलने की स्थिति में मूलभूत इतिहास खतरे में पड़ सकता है और 1972 में लागू संविधान की निरंतरता बाधित हो सकती है। विशेषज्ञों ने बृहस्पतिवार को यह चेतावनी दी।

इस जनमत संग्रह के माध्यम से 'जुलाई राष्ट्रीय घोषणापत्र 2025' नामक सुधार प्रस्तावों के लिए लोगों की सहमति मांगी जा रही है, जिसकी घोषणा यूनुस ने 17 अक्टूबर को राजनीतिक दलों और उनके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय सहमति आयोग के बीच लंबे परामर्श के बाद की थी।

जनमत संग्रह के मतपत्र में 'जुलाई घोषणापत्र' के चार प्रमुख सुधार क्षेत्रों को शामिल करने वाला एक ही प्रश्न है और मतदाताओं से अपील की गई है कि यदि वे प्रस्तावों से दृढ़ता से सहमत हैं तो 'हां' और यदि वे असहमत हैं तो 'नहीं' में वोट दें।

राजनीतिक विश्लेषक और नाटककार इराज़ अहमद ने कहा, बृहस्पतिवार को हो रहे आम चुनाव के साथ-साथ आयोजित जनमत संग्रह में सामने आए प्रस्ताव काफी हद तक गूढ़ प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकतर मतदाता 84 सूत्रीय सुधार पैकेज के बारे में 'अनभिज्ञ' हैं, जिसे जनमत संग्रह पत्र में चार प्रश्नों के माध्यम से संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया गया है।

इराज ने कहा, अगर यह पारित हो जाता है, तो बांग्लादेश की लगभग 55 वर्षों की संवैधानिक निरंतरता वस्तुतः समाप्त हो जाएगी।

बांग्लादेश का संविधान 1972 में लागू हुआ था और अब तक इसमें 17 बार संशोधन किया जा चुका है। हालांकि, आलोचकों का कहना है कि इस बार, यूनुस द्वारा वादा किए गए नए बांग्लादेश के निर्माण के लिए बुनियादी संवैधानिक सिद्धांतों और 'निस्तारित हो चुके मुद्दों' को पलटने के लिए कई प्रस्ताव पेश किए गए हैं।

प्रख्यात अधिवक्ता और संविधान विशेषज्ञ तानिया अमीर ने कहा कि जनमत संग्रह और संवैधानिक सुधार बांग्लादेश के मूलभूत इतिहास और कानूनी विरासत के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ये वस्तुतः हमारे इतिहास को निष्फल कर रहे हैं और बांग्लादेश की 1971 की स्वतंत्रता की कानूनी नींव को काफी हद तक कमतर कर रहे हैं।

प्रख्यात न्यायविद और वकील स्वाधीन मलिक ने कहा, 1972 का संविधान बांग्लादेश की कानूनी रीढ़ है। इसे रद्द करने का प्रयास बांग्लादेश के एक राज्य के रूप में अस्तित्व के कानूनी आधार पर ही सवाल उठाने जैसा है।

यूनुस ने नौ फरवरी को राष्ट्रव्यापी संबोधन में जनमत संग्रह में अपने प्रस्तावित सुधार पैकेज के लिए 'हां' के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया था। हालांकि, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहसिन रशीद सहित कई न्यायविदों ने जनमत संग्रह की वैधता पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि बांग्लादेश के संविधान में इस तरह के जनमत संग्रह का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सरकार ने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवाए और बाद में एक आधिकारिक राजपत्र जारी किया।

विदेश संबंध विशेषज्ञ और पूर्व राजदूत महफूजुर रहमान जैसे विश्लेषकों ने कहा कि 84 बिंदुओं को मान्यता देने वाले चार मुद्दों को मतदाताओं के लिए पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। उनका कहना है कि मतदाताओं को स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि यदि वे 'हां' में वोट देते हैं तो क्या बदलाव होंगे और यदि 'नहीं' में वोट देते हैं तो कौन से बदलाव नहीं होंगे। कानून के प्रोफेसर मलिक और अन्य आलोचकों ने कहा कि चुनाव में 'हां/ना' के आधार पर मतदान करने से मतदाताओं के लिए कई जटिल सुधारों वाले संविधान पर अपना निर्णय लेना मुश्किल हो सकता है और यहां तक कि जानकार मतदाता भी कुछ परिवर्तनों का समर्थन कर सकते हैं लेकिन दूसरों का विरोध कर सकते हैं।

मलिक ने कहा, जुलाई घोषणापत्र में लिए गए अधिकतर निर्णय, जिनमें राजपत्र में प्रकाशित निर्णय भी शामिल हैं, वर्तमान संविधान के विपरीत हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि संविधान अब भी लागू है, इसलिए राष्ट्रपति कानूनी रूप से इस राजपत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं, और यह तब स्वीकार्य हो सकता था जब संविधान को रद्द कर दिया गया होता या मार्शल लॉ के तहत निलंबित कर दिया गया होता।

विधि के एक अन्य प्रोफेसर एस.एम. मासूम बिल्लाह ने कहा कि जुलाई घोषणापत्र में उल्लिखित 84 सुधार प्रस्तावों में से 47 संवैधानिक संशोधन हैं, जबकि 37 को सामान्य कानून या कार्यकारी आदेशों के माध्यम से लागू किया जाना है।

आमंत्रण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

आमंत्रण : बेंगलूरु के जय महादेव युवा संघ केंगेरी उपनगर द्वारा महाशिवरात्रि पर रविवार को चलेघट्टा स्थित आई माता चामुंडेश्वरी मंदिर में 15वें वार्षिकोत्सव में महाशिवरात्रि महोत्सव 'एक शाम भोलेनाथ के नाम' का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में नागौर के भजन गायक महावीर सांखला एवं दिल्ली के मनोज रिया ग्रुप प्रस्तुति देंगे। संघ के सदस्यों ने मारुति मेडिकल्स के प्रमुख महेंद्र मुणोत को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया तथा आमंत्रण पत्रिका भेंट की।

आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने विंडहोक में स्टेडियम बनाने में मदद की: क्रिकेट नामीबिया के अध्यक्ष

नई दिल्ली/भाषा

क्रिकेट नामीबिया के अध्यक्ष रूडी वैन वुरेन ने गुरुवार को कहा कि विंडहोक में नए क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का श्रेय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के चेयरमैन जय शाह को जाता है। नामीबिया 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप का सह मेजबान है।

वैन वुरेन ने एसोसिएट सदस्य देशों को सशक्त बनाने और उनके क्रिकेट बुनियादी ढांचे में सुधार करने के प्रयासों के लिए शाह की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा, आईसीसी ने एसोसिएट सदस्य देशों को सशक्त बनाने की नीति अपनाई है। जय शाह वास्तव में इसमें महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आए हैं। वह विंडहोक में हमारे नए स्टेडियम का दौरा करने आए थे। आईसीसी ने उस स्टेडियम के निर्माण में हमारी बहुत मदद की।आईसीसी ने 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक स्टेडियमों का निर्माण किया है जिसका फायदा नामीबिया जैसे देश को भी मिल रहा है। वैन वुरेन ने कहा, अब हमारे पास अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। आईसीसी के सहयोग से नामीबिया जैसे अफ्रीकी देश आगे बढ़ रहे हैं और अंतर धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। हमें इन अवसरों का फायदा उठाना चाहिए और दुनिया को यह दिखाना चाहिए कि एसोसिएट सदस्य क्रिकेट का भविष्य हैं।

अंतरिक्ष में रहने से खोपड़ी के भीतर मस्तिष्क की स्थिति बदल सकती है : नया अध्ययन

तल्हासी (अमेरिका)। अंतरिक्ष में जाना मानव शरीर के लिए चुनौतीपूर्ण होता है और एक नए अध्ययन में पाया गया है कि अंतरिक्ष यात्रा के बाद मस्तिष्क खोपड़ी के भीतर ऊपर और पीछे की ओर खिसकता है तथा उसका आकार भी कुछ हद तक बदल जाता है।

शोधकर्ताओं के अनुसार, जो लोग अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहे, उनमें ये बदलाव अधिक स्पष्ट थे। नासा की लंबी अंतरिक्ष यात्राओं की योजनाओं और पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों से आगे आम लोगों तक अंतरिक्ष यात्रा के विस्तार के मद्देनजर ये निष्कर्ष अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शरीर और मस्तिष्क के द्रवों को नीचे की ओर खींचता है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में शरीर के द्रव सिर की ओर खिसकते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों का चेहरा सूजा हुआ दिखाई देता है। सामान्य गुरुत्वाकर्षण में मस्तिष्क, मस्तिष्कमेरु (सेरेब्रोस्पाइनल) द्रव और आसपास के ऊतक संतुलन की स्थिति में रहते हैं, लेकिन सूक्ष्म गुरुत्व (माइक्रोग्रैविटी) में यह संतुलन बदल जाता है।

गुरुत्वाकर्षण के अभाव में मस्तिष्क खोपड़ी के भीतर 'तैरने' लगता है और आसपास के मुलायम ऊतकों तथा स्वयं खोपड़ी से विभिन्न प्रकार के दबावों का सामना करता है। पहले के अध्ययनों में पाया गया था कि अंतरिक्ष यात्रा के बाद मस्तिष्क खोपड़ी में ऊपर की ओर स्थित दिखाई देता है, लेकिन अधिकांश शोध औसत या पूरे मस्तिष्क के माप पर केंद्रित थे, जिससे अलग-अलग हिस्सों में होने वाले सूक्ष्म बदलाव छिप सकते हैं।

शोध दल ने 26 अंतरिक्ष यात्रियों के मस्तिष्क के एमआरआई स्कैन का विश्लेषण किया, जिन्होंने कुछ सप्ताह से लेकर एक वर्ष से अधिक समय अंतरिक्ष में बिताया था। अंतरिक्ष यात्रा से पहले और बाद के स्कैन की तुलना करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की खोपड़ी को आधार बनाकर संरेखण किया गया।

मस्तिष्क को एक इकाई के रूप में देखने के बजाय उसे 100 से अधिक हिस्सों में विभाजित कर प्रत्येक क्षेत्र में हुए बदलाव को अलग-अलग मापा गया। इससे वे पैटर्न सामने आए जो पूरे मस्तिष्क के औसत विश्लेषण में दिखाई नहीं देते थे।

अध्ययन में पाया गया कि अंतरिक्ष यात्रा के बाद मस्तिष्क लगातार ऊपर और पीछे की ओर खिसकता है।

अंतरिक्ष में बिताया गया समय जितना अधिक था, बदलाव भी उतना ही अधिक था। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लगभग एक वर्ष बिताने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से के कुछ क्षेत्र दो मिलीमीटर से अधिक ऊपर खिसक गए, जबकि अन्य हिस्सों में अपेक्षाकृत कम बदलाव देखा गया। शोधकर्ताओं के अनुसार, खोपड़ी जैसी सीमित जगह में यह दूरी भी महत्वपूर्ण है।

गति और संवेदना से जुड़े मस्तिष्कीय क्षेत्रों में सबसे अधिक बदलाव देखे गए। मस्तिष्क के दोनों ओर स्थित संरचनाएं मध्य रेखा की ओर खिसकीं, जिससे दोनों गोलार्द्धों में विपरीत दिशा में परिवर्तन हुआ। यही कारण है कि पूरे मस्तिष्क के औसत विश्लेषण में ये बदलाव स्पष्ट नहीं हो पाए थे।

आज जीवित कोई भी जीव 'आदिम' नहीं है, फिर भी कई जीवों को ऐसा क्यों कहा जाता है?

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मैरीलैंड। हम मनुष्य लंबे समय से स्वयं को विकास (इवोल्यूशन) की पराकाष्ठा मानते रहे हैं। अन्य प्रजातियों को अक्सर आदिम या प्राचीन कहा जाता है और उच्च एवं निम्न जीव जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है।

मानव-केंद्रित इस दृष्टिकोण को 1866 में और बल मिला, जब जर्मन वैज्ञानिक अन्स्र्ट हैकेल ने जीवन-वृक्ष (ट्री ऑफ लाइफ) का एक प्रारंभिक चित्र बनाया, जिसमें मनुष्य को स्पष्ट रूप से शीर्ष पर दिखाया गया। इस चित्रण ने यह धारणा लोकप्रिय बनाई कि विकास का अंतिम लक्ष्य मनुष्य हैं।

आधुनिक विकासवादी जीवविज्ञान इस सोच को नकारते हैं। उनके अनुसार विकास में कोई पदानुक्रम नहीं है। आज जीवित सभी प्रजातियां-चिंपैंजी से लेकर बैक्टीरिया तक-एक-दूसरे की संबंधी हैं, जिनकी विकास-रेखाएं समान रूप से लंबी हैं; वे किसी की पूर्वज या उत्तराधिकारी नहीं हैं।

इसके बावजूद आदिम जैसी अवधारणाएं वैज्ञानिक पत्रिकाओं और विज्ञान पत्रकारिता में अब भी दिखाई देती हैं। मैंने अपनी नई पुस्तक अंडरस्टैंडिंग द ट्री ऑफ लाइफ में लिखा है कि किसी भी वर्तमान प्रजाति को आदिम, प्राचीन या सरल कहना मूलतः भ्रामक है और विकास का इतिहास जटिल, गैर-पदानुक्रमित और परस्पर जुड़ा हुआ है।

अंडे देने वाले स्तनधारी मोनोट्रीम कहलाते हैं और उन्हें अक्सर सबसे आदिम जीवित स्तनधारी बताया जाता है। इस समूह में प्लैटिपस और चार प्रजातियों के इकिडना शामिल हैं। उनका अंडे देना एक प्राचीन विशेषता है, जो सरीसृपों में भी है।

लेकिन प्लैटिपस में कई विशिष्ट आधुनिक अनुकूलन यानी एडैप्टेशन भी हैं जैसे तैरने के लिए जालीदार पैर और चोंच में विशेष इलेक्ट्रोरिसेप्टर, जो कीचड़ में शिकार का पता लगाते हैं। नर प्लैटिपस के पैरों में विषैले कांटे भी होते हैं। इकिडना को भी अक्सर आदिम समझा जाता है, खासकर क्योंकि वे शिशु को जन्म नहीं देते लेकिन उनके पास सुरक्षात्मक कांटे, खोदने के लिए शक्तिशाली पंजे, संवेदनशील चोंच और लंबी चिपचिपी जीभ जैसी विशेषताएं हैं, जिनकी मदद से वे दीमक और चींटियों का शिकार करते हैं। दीमक के ढेर में भोजन खोजने की प्रतिस्पर्धा में इकिडना मनुष्य से कहीं बेहतर साबित होंगे।

ऑस्ट्रेलिया के अन्य स्तनधारी जैसे कंगारू, कोआला और वॉम्बैट, मार्सुपियल (थैलीदार स्तनधारी) हैं और वे भी कभी-कभी आदिम कहे जाते हैं। ये छोटे और कम विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जो मां की थैली में विकसित होते हैं। हालांकि यह तरीका मनुष्य से अलग है, लेकिन इसके अपने फायदे हैं जैसे कंगारू एक साथ विकास के अलग-अलग चरणों में तीन शिशुओं का पोषण कर सकते हैं।

विकास-वृक्ष (फाइलोजेनी) में मार्सुपियल या मोनोट्रीम को अक्सर नीचे या बाईं ओर दिखाया जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे अधिक प्राचीन या कम विकसित हैं। ये वृक्ष संबंध दिखाते हैं, न कि श्रेष्ठता। जैसे आपका कोई दूर का चचेरा भाई आपसे आदिम नहीं होता, वैसे ही कोआला या इकिडना को भी केवल उनकी स्थिति के आधार पर आदिम कहना गलत है।

अक्सर इन वृक्षों का केंद्र प्लेसेंटल स्तनधारी (जैसे मनुष्य, प्राइमेट, मांसाहारी, कृंतक आदि) होते हैं, इसलिए तुलना के लिए कुछ मार्सुपियल प्रजातियों को शामिल किया जाता है।

लोग सोशल मीडिया के 'क्लीनकल' आदी नहीं हो सकते: इंस्टाग्राम प्रमुख

लॉस एंजिलिस/एपी

मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम के प्रमुख एडम मोसेरी ने लॉस एंजिलिस में सोशल मीडिया से जुड़े एक मामले में गवाही देते हुए कहा कि वह इस विचार से सहमत नहीं हैं कि लोग सोशल मीडिया मंचों के 'क्लीनिकल' आदी हो सकते हैं।

यह मामला उन आरोपों पर आधारित है जिनमें वादियों ने सोशल मीडिया कंपनियों को, उनके मंचों का उपयोग करने वाले बच्चों को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराने की मांग की है। इस मुकदमे में मेटा प्लेटफॉर्म्स और गूगल का यूट्यूब भी प्रतिवादी हैं, जबकि टिकटॉक और स्नैप पहले ही समझौता कर चुके हैं।

लॉस एंजिलिस का यह मामला 20 वर्षीय एक युवती पर केंद्रित है, जिसकी पहचान 'केजीएम' के रूप में की गई है। उसका मुकदमा यह तय कर सकता है कि सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ दायर हजारों ऐसे ही मुकदमों का क्या परिणाम होगा।

मोसेरी ने बुधवार को कहा कि 'क्लीनिकल एडिक्शन' होने और समस्या उत्पन्न करने वाले उपयोग के बीच अंतर करना जरूरी है।

'क्लीनिकल एडिक्शन' ऐसी लत को कहा जाता है जिसे चिकित्सकीय रूप से एक मानसिक या व्यवहारिक विकार के रूप में पहचाना गया हो और जिसके लिए पेशेवर इलाज की आवश्यकता हो।

हालांकि वादी पक्ष के वकील ने एक पुराने पॉडकास्ट साक्षात्कार का हवाला दिया, जिसमें मोसेरी कथित रूप से विपरीत बात कहते नजर आए थे। इस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उस समय उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल संभवतः यूं ही आम बोलचाल की भाषा में किया था, जैसा कि लोग अक्सर कर देते हैं। उन्होंने कहा कि वह चिकित्सा विशेषज्ञ होने का दावा नहीं कर रहे, लेकिन उनके बहुत करीबी किसी व्यक्ति को गंभीर 'क्लीनिकल लत' का अनुभव हुआ है, इसलिए वह अपने शब्दों को लेकर सावधानी बरतते हैं।

मोसेरी ने कहा कि वह और उनके सहयोगी 'समस्या उत्पन्न करने वाला उपयोग' शब्द का इस्तेमाल उस स्थिति के लिए करते हैं, जब कोई व्यक्ति इंस्टाग्राम पर उतना अधिक समय बिताता है, जितना वह खुद उचित नहीं मानता और ऐसा निश्चित रूप से होता है।

मोसेरी ने कहा, हम अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ ही न्यूनतम सेंसरशिप भी रखना चाहते हैं।

तमिलनाडु में श्रमिक संगठनों की हड़ताल से बंदरगाह संचालन प्रभावित, श्रमिकों ने प्रदर्शन किया

थूथुकुडी। केंद्र सरकार की कथित श्रमिक-विरोधी और किसान-विरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के कारण तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बृहस्पतिवार को श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। थूथुकुडी और चेन्नई में बंदरगाह संचालन इस हड़ताल से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ और 'सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस' (सीआईटीयू) सहित प्रमुख श्रमिक संगठनों ने प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। तूतीकोरिन में प्रदर्शनकारियों की एक सभा को संबोधित करते हुए सीआईटीयू के जिला सचिव रसेल ने दावा किया कि इस हड़ताल को व्यापक समर्थन मिला है, जिसमें देश भर में 30 करोड़ से अधिक किसान और मजदूर भाग ले रहे हैं। रसेल ने कहा कि देश के सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों और किसान संगठनों ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया है और यह केंद्र सरकार के अधिकांश विभागों में पूरी तरह से जारी है। सीआईटीयू नेता ने दावा किया कि थूथुकुडी स्थित वी ओ चिदंबरनार बंदरगाह पर परिचालन व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है।

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company, 6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51 and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**,
(*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.
HEAD OFFICE : DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT, New Media Company, 6/4, Cantonment Station Road, Bangalore 560051. Editorial : 080-25363030 / 9945488003. For Advertisement : 9945488002 - email : news@dakshinbharat.com/**RNI No. 58061/93.**